



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 666]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2009/कार्तिक 27, 1931

No. 666]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2009/KARTIKA 27, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(रक्षोपाय, सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशक का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2009

अंतिम जांच परिणाम

विषय : भारत में लीनियर अल्काइल बेंजीन के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जाँच

सा.का.नि. 832(अ).—सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 एवं उसके तहत बनाए गए सीमा-शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आकलन) नियम, 1997 को ध्यान में रखते हुए ।

क. प्रक्रिया

1. (i) मै. रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि., मुम्बई, (ii) मै. तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लि., चेन्नई (iii) मै. निरमा लि., अहमदाबाद, (iv) मै. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि., नई दिल्ली (समर्थक) द्वारा भारत में लीनियर अल्काइल बेंजीन के आयातों के संबंध में रक्षोपाय शुल्क लगाने की माँग करते हुए सीमा-शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आकलन) नियम, 1997 (जिसे आगे "रक्षोपाय नियम" कहा गया है) के नियम 5 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि लीनियर अल्काइल बेंजीन के संबंधित आयातों के कारण भारत में लीनियर अल्काइल बेंजीन के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हो रही है और/अथवा गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न हो रहा है। इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि नियम 5 की अपेक्षाएँ पूरी हो गई हैं, लीनियर अल्काइल बेंजीन के आयातों के खिलाफ रक्षोपाय जाँच 19-12-2008 की जाँच शुरुआत संबंधी सूचना के तहत शुरू की गई थी जिसे उसी दिन भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।

2. प्रमुख निर्यातक देशों की सरकारों को नई दिल्ली स्थित उनके दूतावासों के जरिए सूचना की एक प्रति भेजी गई थी । जाँच शुरुआत संबंधी सूचना की एक प्रति निम्नलिखित समस्त ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को भी भेजी गई थी :

घरेलू उत्पादक :

- (i) मै. रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि. मुम्बई
- (ii) मै. तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लि., चेन्नई
- (iii) मै. निरमा लि., अहमदाबाद
- (iv) मै. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि., नई दिल्ली (समर्थक)

आयातक

- (i) फेना प्रा. लि., ए-67 एवं 68, मेट्टूपलायम, पीआईपीडीआईसी औद्योगिक क्षेत्र, पाण्डिचेरी-605009
- (ii) स्किल डाइकेम, ग्राम पंचपारा, डाकघर- राधादासी-711309, हावड़ा, प. बंगाल
- (iii) साई सल्फोनेट्स प्रा. लि. 21, प्रिसेप स्ट्रीट, कोलकाता- 700072, प. बंगाल
- (iv) रोहित सर्फैक्टेंट्स प्रा. लि. (धारी), केडीसी-चौबेपुर यूनिट, 117/एच-2/202, पांडु नगर, कानुपर-200005, उत्तर प्रदेश

निर्यातक

- i) ईरान केमिकल इण्डस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कं., नं. 91, सईदी स्ट्रीट, अफ्रीका एवेन्यू, तेहरान (19679), ईरान
- ii) गल्फ फराबी पेट्रोकेमिकल कं., अल-जुबैल इण्डस्ट्रियल सिटी 31961, पी. ओ. बॉक्स 11763, सऊदी अरब साम्राज्य
- iii) सीफ लिमिटेड, कतर, सीफ लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स : 50077, मेसाईद, स्टेट ऑफ कतर
- iv) कोलमार ग्रुप एजी, लॉबेहॉफ, मेटलस्ट्रेस 9,6300 जुग, स्विट्जरलैंड

3. उसी दिन सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों तथा आयातकों एवं निर्यातकों को प्रश्नावलियाँ भी भिजवाई गई थीं और उनसे 30 दिन के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ।

4. निम्नलिखित पक्षकारों से उन पर हितबद्ध पक्षकारों के रूप में विचार किए जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था और समस्त अनुरोध स्वीकार किए गए थे ।

- 1 मै. फैशन सूटिंग (प्रा.) लि.
3, छाबड़ा मेशन, पुरी रोड, भीलवाड़ा-311001
- 2 मै. श्री यूनिकॉन ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.
बीएस, एपीजी, 130 मुम्बई समाचार मार्ग, मुम्बई-400023
- 3 ए आर सल्फोनेट्स प्रा. लि.
प्लॉट नं. एन-41, एडिशनल अम्बरनाथ, एमआईडीसी आनंद नगर, जिला थाणे-421501, महाराष्ट्र
- 4 तमिलनाडु स्मॉल स्केल सोप एंड डिटर्जेंट्स
चेतु “ डी ” अम्पा, चतुर्थ तल, नं. 37, पुराना नं. 110
नेल्सन मणिकेम रोड, चेन्नई-600029
- 5 शांति नाथ डिटर्जेंट्स (प्रा.) लि.
पी-15, कलाकार स्ट्रीट, कोलकाता- 700007
- 6 राजाराम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज
14, अजीज नगर, सेकेंड स्ट्रीट, कोडमबक्कम, चेन्नई-600024
- 7 किशोर्स सन्स डिटर्जेंट्स प्रा. लि.
15-9-469, महानूनगंज, हैदराबाद-500012 (आंध्र प्रदेश), भारत
- 8 एडवांस सर्फैक्टेंट्स इंडिया लि.
511/2/1, रजोकरी, नई दिल्ली-110038
- 9 ए. आर. स्टैनकेम प्रा. लि., एक्सपोटर्स एंड मैन्यूफैक्चरर्स
ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, द्वितीय तल, कोक एंड काल्वे बिल्डिंग
कोलकाता-700001
- 10 न्यू इंडिया डिटर्जेंट्स लि.
ए-2/25 मॉडल टाउन-1, दिल्ली-110009

- 11 मै. स्मॉल स्केल डिटर्जेंट
43 यूरोपीयन एसियम लेन, कोलकाता- 700016
- 12 स्टैंडर्ड सर्फैक्टेंट्स लि.
8/5 आर्य नगर, कानपुर-208002
- 13 गोरा मल हरि राम लि.
39, नजफगढ़ रोड, औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली-15
- 14 डिटर्जेंट्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन,
148, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स-1,
नई दिल्ली-110002
- 15 बड़कुर सर्फैक्टेंट्स प्रा. लि.
यूनिटॉप हाउस, ईस्ट वेस्ट एस्टेट, सफेद पूल,
अंधेरी कुर्ला रोड,
मुम्बई-400072
- 16 इसरो प्रोडक्ट
यूनिटॉप हाउस, ईस्ट वेस्ट एस्टेट, सफेद पूल, अंधेरी कुर्ला रोड,
मुम्बई-400072
- 17 एस. कुमारस डिटर्जेंट्स प्रा. लि.
4-डी स्थानीय विपणन केंद्र, ए ब्लॉक, रिंग रोड, नारायणा
नई दिल्ली-110028
- 18 सासी-कैम
59 तथा 60, डीएसआईडीसी, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, ओखला फेज-I
नई दिल्ली-110020
- 19 हिपोलीन लि.
मधुबन, चौथा तल, एलिस ब्रिज
अहमदाबाद-380006
- 20 ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिटर्जेंट मैन्यूफैक्चरर्स
511/2/1, रजोकरी, नई दिल्ली

- 21 महाराष्ट्र स्मॉल स्केल सोप डिटर्जेंट्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
श्री वीराबाई मा निवास
शास्त्री नगर स्ववेयर, नागपुर-8
महाराष्ट्र
- 22 गुजरात स्मॉल स्केल डिटर्जेंट्स मैनु. एसोसिएशन
मार्फत किशोर सोप इन्ड;
माहेश्वरी मिल रोड
तावडीपुरा, शाहीबाग
अहमदाबाद-380004
- 23 पावर सोप्स लि.
62बी, नॉर्थ बोग रोड, टी नगर, चेन्नई-600017
- 24 मै. भास्कर वेंकटेश कोडक्स प्रा. लि.
भवानी कॉम्प्लेक्स
35, हनुमानगंज, जुमेराती कॉर्नर के निकट, भोपाल-462001 (म. प्र.)
- 25 मै. एडॉस कन्ज्यूमर केयर लि.
जालान काम्पाउंड
बॉम्बे हाइवे, एन एच सं. 6, बिपरन्नपारा, हावड़ा-711411
- 26 मै. प्रबु सोप वर्क्स
पो.बॉ. सं. 5115, 3/ए1, थईर इटेरी रोड
कनप्पन नगर,
रत्नापुरी (पी.ओ.), कोयम्बतूर-641027
- 27 मै. श्रीराम भारत कैमिकल्स एंड डिटर्जेंट्स (प्रा.) लि.
1/56, संजय गाँधी नगर
नोचीपलायम रोड,
46, पंधुर गाँव, एरोड-638002
- 29 मै. साबरी डिटर्जेंट्स
191, वलपाराई रोड,
अवलचिन्नमपलायम
जामिन कोट्टमपट्टी, पोलाची-642123

- 30 मै. एस एस इंटरप्राइजेज
सं. 43, सिडको इंड. एस्टेट
डिंडिगुल-624003
- 31 मै. मान कैमिकल्स
20/1, शिवकामी इल्लम,
लक्ष्मी सुंदरम कोलोनी
एमएसपी स्कूल ग्राउंड के पीछे
डिंडिगुल-624005
- 32 मै. शक्ति ट्रेडर्स
सं. 5/810, मल्लीगाई रोड
कोट्टुरवु नगर
डिंडिगुल- 624005
- 33 मै. शिवा सोप वर्क्स
नन्थावाना पट्टी
डिंडिगुल-624005
- 34 मै. नेशनल सोप्स कं.
138/1, सम्मम पलायम पिरिवु
नसियानुर रोड
वल्लारसम्पट्टी नल्ल रोड, नसियानुर (पी.ओ.)
इरोड-638107, तमिलनाडु
- 35 मै. श्री मानाकुला विनायगा कैमिकल्स
आर एस सं. 89/1-एफ एंड डी, पन्निथिट्टु रोड
किरुममपक्कम, पांडिचेरी-607402
- 36 मै. सिल्वर कैमिकल्स
1/255, मेन रोड
वलायमकुलम
मदुरई-625022, तमिलनाडु

- 37 मै. राजा कैमिकल वर्क्स
137, सामी अय्यर न्यू स्ट्रीट
कोयम्बतूर-641001
- 38 मै. श्री पुष्पम इंडस्ट्रीज
आर एस सं. 121/1 एवं 63/7,
माडागडीपेट एवं तिरुबुवानी गाँव
तिरुबुवानी पोस्ट, पाँडिचेरी-605107
- 39 मै. लिंगम कैमिकल इंडस्ट्रीज
8/55, अम्बई रोड, अलंगुलम-627851
तिरुल्लैलवेली, तमिलनाडु
- 40 मै. आनंद कैमिकल्स
13/4, कामराजर नगर
अवनीयापुरम (पी.ओ.)
अयुनपप्पाकुडी
मुदुरै-625012 (तमिलनाडु)
- 41 मै. हाइटेक इंडिया
सं. 1, वेंगुर रोड
तिरुवैरुम्बुर
त्रिची-620013
- 42 मै. फ्लोरा कैमिकल्स
2/226, अम्माची अम्मान कोइल स्ट्रीट
उथंगुडी, मदुरै-625107
तमिलनाडु
- 43 मै. देवी क्रॉपसाइंस प्रा. लि.
पो. बॉ. सं. 274, 29-ए,
वर्कशॉप रोड, मदुरै-625001
- 44 मै. षण्मुगा इंडस्ट्रीज
139-एबीसी, सुन्दक्कामुथुर रोड
सेल्वापुरम
कोयम्बतूर-26

- 45 मै. साइमोस प्रोडक्ट्स
4/139, अयन्नारपुरम मेन रोड,
पनइयुर (पी.ओ.) मदुरै-625009
 - 46 मै. रेसिमे प्रोडक्ट्स
2/221, अय्यानर कोविल स्ट्रीट
उथंगुडी, मदुरै-625017
 - 47 मै. आर्किड कैमिकल्स
183, नेदुंगुलम रोड
पोट्टापलायम
सिवगना जिला 630611
तमिलनाडु
 - 48 मै. मुथुकानी इंडस्ट्रीज
2/104(1)- न्यू कोलोनी
अन्दीपट्टी-पी.ओ.
अलंगुलम-627851
 - 49 मै. वरदान डिटर्जेंट प्रा. लि.
प्लॉट नं. 131, सेक्टर-24
फरीदाबाद-121005
 - 50 मै. रियनो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.
बी-93, मायापुरी फेज-1
नई दिल्ली-64
5. कुछेक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था । निर्धारित अवधि के भीतर जाँच पूरी करने की समय-सीमाओं को ध्यान में रखने के बाद समय विस्तार के अनुरोधों की अनुमति दी गयी थी और पक्षकारों को तदनुसार सूचित किया गया था । इनके अलावा, हितबद्ध पक्षकार बनने के किसी विशिष्ट अनुरोध के बिना विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । उनके द्वारा उठाए गए कई मुद्दे अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के समान हैं । इन पर तदनुसार विचार किया गया है ।

6. जाँच शीघ्रता से पूरी कर प्रारंभिक जांच परिणाम 30 जनवरी, 2009 को जारी किए गए थे । तथापि, कोई अनंतिम रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया गया है ।

7. 23 जुलाई को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गयी थी जिसकी सूचना वेबसाइट पर नोटिस उपलब्ध कराने के अलावा समस्त हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी । जिन हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया था उन सभी से सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आकलन) नियम, 1997 के नियम-6 के उप नियम (6) के अनुसार मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था । एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर किए गए लिखित अनुरोध की प्रति अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी । हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों पर उत्तर, यदि कोई हो, दायर करने का अवसर भी प्रदान किया गया था । हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित अनुरोधों में या उत्तरों में व्यक्त किए गए समस्त विचारों की जांच की गई थी और उन पर उचित निर्धारण करने में विचार किया गया था ।

8. घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादन, बिक्री तथा क्षति के अन्य मापदंडों के बारे में प्रस्तुत सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों में मौके पर जाकर सत्यापन किया गया था । इसके अलावा, लागत संबंधी आंकड़ों का भी सत्यापन किया गया है और इन्हें स्वतंत्र लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया गया है । सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय रूपांतरण सार्वजनिक फाइल में रखा गया है ।

9. सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं आकलन) नियम, 1997 के नियम 11 के उप नियम (1) के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने अधिसूचना सं. 123/2009-सी.शु. (एनटी), दिनांक 18 अगस्त, 2009 के तहत भारत में लीनियर अल्काइल बेंजीन के आयातों के बारे में रक्षोपाय जांच से संबंधित अंतिम जांच परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए जांच अवधि 18 नवम्बर, 2009 तक बढ़ाई थी जिसमें यह दिन भी शामिल है ।

10. चूँकि हितबद्ध पक्षकारों की संख्या अधिक है, इसलिए इन हितबद्ध पक्षकारों के अलग-अलग अनुरोधों को समेकित रूप में रिकॉर्ड किया जा रहा है । तथापि, जिन हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया था, उनके द्वारा किए गए अनुरोधों को संक्षेप में अंतिम जांच परिणामों में अलग-अलग दर्ज किया जा रहा है ।

भारत के घरेलू उद्योग के विचार

11. आवेदकों के विचार संक्षेप में निम्नानुसार हैं :

क) उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ विवरण शीर्ष 38170011 के अंतर्गत आने वाले “ सभी प्रकार रके लीनियर एल्काइल बेंजीन, मिक्सड अल्काइल बेंजीन ” के रूप में परिभाषित किया गया है। वाणिज्यिक बाजारी भाषा में उपर्युक्त उत्पाद को सामान्यतः “ लीनियर एल्काइल बेंजीन ” (संक्षेप में एलएबी) कहा जाता है। सम्बद्ध वस्तु का प्रयोग लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फॉनिक एसिड अथवा लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फॉनिक एसिड के सोडियम लवण के विनिर्माण में किया जाता है। सभी लीनियर एल्काइल बेंजीन एवं सम्बद्ध वस्तुएं सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय शीर्ष 38.17 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं।

ख) नियम 2(ग) में “ संवर्धित मात्रा ” की अवधारणा की व्याख्या की गयी है जिसका तात्पर्य आयातों में समग्र रूप में या घरेलू उत्पादन की तुलना में वृद्धि से है। आयातों में न केवल समग्र रूप में अपितु उत्पादन एवं माँग की तुलना में भी वृद्धि हुई है। आयात, जो वर्ष 2004-05 में अत्यंत कम 9854 मी. टन के हुए थे उनमें वर्ष 2007-08 में साढ़े चार गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा, अप्रैल, 2008-मार्च, 2009 की नवीनतम अवधि में मात्रा में 62% की वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग की समस्या बढ़ गई है। आयातों की प्रवृत्ति की जांच से स्पष्टतः यह पता चलेगा कि आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और मात्राएँ वर्ष 2005-06 को छोड़कर प्रतिवर्ष दोगुनी हुई हैं। वर्ष 2009-10 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) में आयात पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए 11545 मी. टन से आगे और बढ़कर 17783 मी. टन के हो गए अर्थात् 54% की भारी वृद्धि हुई। वर्ष 2008-09 की प्रथम छमाही (25001 मी. टन) और दूसरी छमाही (48629 मी. टन) के बीच आयातों की तुलना से इस बात की स्पष्टतः पुष्टि होती है कि आयातों के संबंध में स्थिति वर्ष की परवर्ती छमाही में खराब हुई है जब वृद्धि 94% की हुई है।

ग) जहाँ तक उत्पादन के बारे में आयात की मात्रा का संबंध है, आयात जो घरेलू उद्योग द्वारा कुल उत्पादन के मामूली 2.66% थे, बढ़कर 2006-07 में 6.36%, तत्पश्चात् वर्ष 2007-08 में बढ़कर 13.46 और बाद में वर्ष 2008-09 में बढ़कर 25.70% हो गए।

घ) इस प्रकार, आंकड़ों से निःसंदेह यह सिद्ध होता है कि संबद्ध वस्तु के आयातों में समग्र रूप में, वृद्धि दर तथा घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन के संबंध में भारी वृद्धि हुई है। यह नोट करना प्रासंगिक है कि वर्ष 2008-09 में वृद्धि का यह परिदृश्य इस तथ्य के बावजूद उत्पन्न हुआ है कि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में वैश्विक मंदी व्याप्त थी।

ड.) घरेलू उद्योग द्वारा “ गंभीर क्षति ” के मुद्दे पर डीजी का ध्यान रक्षोपाय नियमावली के अनुबंध के पैराग्राफ 8 की ओर आकर्षित किया गया जिसके अनुसार डीजी द्वारा केवल “ वस्तुनिष्ठ तथा परिमाण निर्धारण योग्य स्वरूप ” के सभी संगत कारकों का मूल्यांकन किया जाना अनिवार्य है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि आयातों में आकस्मिक तथा अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें गंभीर क्षति का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2004-05 में घरेलू उद्योग की कुल बिक्री 211155 मी. टन तक हुई थी जिसमें कुल माँग में वृद्धि के बावजूद निरंतर कमी आती रही है। वर्ष 2008-09 में अब तक की सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई जब कुल बिक्री गत वर्ष के 184212 मी. टन के स्तर से घटकर 168744 मी. टन के स्तर पर आ गई। कुल घरेलू उत्पादन में आवेदक का हिस्सा लगभग 72% बनता है और वह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा 6(ख)(ii) के अनुसार “ घरेलू उद्योग ” है।

(च) आयात वर्ष 2004-05 में 3.82% की तुलना में वर्ष 2008-09 में बढ़कर 21.18% हो गए हैं जिससे घरेलू उद्योग का 17.36% बाजार हिस्सा कम हो गया है। यदि केवल आवेदक घरेलू उद्योग की बिक्री को ही लिया जाए तो आयातों द्वारा लिया गया बाजार हिस्सा और भी अधिक होगा। भारत में एलएबी के अधिकांश आयात हिस्सा कतर, ईरान तथा सऊदी अरब से होते हैं। इन देशों तथा अन्य मध्य-पूर्वी देशों की एलएबी की संयुक्त क्षमताओं का लगभग 70% हिस्सा निर्यातों के लिए निर्धारित होता है। इन देशों की भौगोलिक निकटता तथा भारत में एलएबी क्षेत्र में भारी मंदी के कारण इन देशों के लिए भारत एक आकर्षक निर्यात गंतव्य बन गया है। मिस्र में एक और संयंत्र की संस्थापना के साथ इस क्षमता में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

(छ) वर्ष 2008-09 में घरेलू उद्योग का उत्पादन वर्ष 2007-08 में 338010 मी. टन के स्तर से घटकर 286549 मी. टन रह गया है जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उत्पादन में कमी के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है। वर्ष 2008-09 के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में अत्यधिक गिरावट आई है। वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग क्रमशः 113% तथा 109% के अच्छे स्तर पर था जो वर्ष 2008-09 में घटकर मात्र 76% रह गया है।

(ज) यह उल्लेखनीय है कि एलएबी उद्योग में प्रति इकाई औसत निर्धारित लागत को कम करने के लिए संयंत्रों का क्षमता उपयोग के उच्चतम स्तरों पर प्रचालन करना आवश्यक है। क्षमता उपयोग में कमी का सीधा प्रभाव उनकी लाभप्रदता तथा दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर पड़ता है। मौजूदा मामले में भी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग प्रभावित हुआ है जिसके कारण क्षमता उपयोग में कमी आई और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई।

(झ) बढ़े हुए आयातों और परिणामतः क्षमता के कम उपयोग के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में भारी कमी आई है। घरेलू उद्योग सकारात्मक लाभ स्तर से *** (100 पर सूचीबद्ध) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में हानि की स्थिति में पहुँच गया है। वर्ष 2008-09 में घरेलू उद्योग का लाभ नाममात्र रहा है अतः सूचीबद्ध संख्या शून्य है।

(ञ) क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत निवल बिक्री आय में वृद्धि हुई है। तथापि घरेलू उद्योग की औसत निवल बिक्री आय में वृद्धि को इसे लागत में वृद्धि का सीधा प्रभाव कहा जा सकता है।

(ट) जहाँ तक एलएबी के प्रयोक्ताओं के हितों का संबंध है, यह अनुरोध किया गया था कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय यहाँ लागू नहीं होता क्योंकि इसमें डीजी के लिए सार्वजनिक हित के मुद्दों पर आधारित आदेश पारित करना या उसे ऐसे अधिकार देना अनिवार्य नहीं बनाया गया है। हितबद्ध पक्षकारों को डीजी को अपने परिणामों में सार्वजनिक हित के मुद्दों का समाधान करने हेतु बाध्य करने का कानूनी अधिकार न होने संबंधी तथ्य के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना यह अनुरोध किया गया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने अपने मामले के समर्थन में कोई साक्ष्य या जानकारी प्रस्तुत नहीं की है।

(ठ) किसी भी आयातक (एचयूएल को छोड़कर) ने डीजी के दिनांक 7.7.09 के पत्र द्वारा माँगी गई सूचना का उत्तर नहीं दिया है। बल्कि एचयूएल ने भी केवल चुनिंदा ब्रांडों के लिए ही सूचना प्रस्तुत की है जिससे डीजी के लिए कोई सार्थक विश्लेषण करना असंभव हो गया है। इसके अलावा, इस प्रकार के निर्णय देने का कोई आधार नहीं है कि “यदि एलएबी पर शुल्क अधिरोपित किए गए तो इससे 20 करोड़ परिवार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे”।

(ड) आयातकों/प्रयोक्ताओं ने इस संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है कि कच्चे माल की कीमतों में समग्र वृद्धि के कारण एलएबी की कीमतों में वृद्धि होने से डिटर्जेंट उद्योग में रोजगार की स्थिति किस प्रकार प्रभावित हुई। यह साफ है कि आयातक पहले से संतुष्ट एलएबी उद्योग की लागत पर अपने लाभ मार्जिनों की रक्षा करने के लिए रोजगार और बड़े सार्वजनिक हित के मुद्दों का केवल बहाना बना रहे हैं। वास्तविकता यह है कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से घरेलू उत्पादक न केवल बढ़े हुए आयातों का सामना करने में सक्षम होंगे अपितु इससे दीर्घकाल में एलएबी के क्रेताओं सहित अंतिम प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा।

(ढ) बढे हुए आयातों, लाभ में गिरावट तथा नियोजित पूँजी पर कम आय के कारण बने दबाव के परिणामस्वरूप हुए मालसूचियों के जमाव के चलते घरेलू उद्योग के अनेक संयंत्र बंद हो गए थे । डीजी को इससे संबंधित ब्यौरा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराया गया है । किसी भी स्थिति में हमारा यह अनुरोध है कि डीजी (रक्षोपाय) के अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की जाँच कर ली गई है कि बाजारी स्थितियों के कारण घरेलू उद्योग लंबी अवधि के लिए बंद रहा है ।

(ण) यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा केवल कानून के अनुसार एलएबी के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु अनुरोध किया गया है ताकि वे बढे हुए आयातों के कारण उत्पन्न हुई प्रतिस्पर्धा की स्थिति का सामना कर सकें । शुल्क के अधिरोपण का प्रयोजन बढे हुए आयातों के कारण उत्पन्न हुई प्रतिस्पर्धा की स्थिति का सामना करने के लिए घरेलू उद्योग को पर्याप्त समय प्रदान करना है । यदि घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता उपयोग के पूर्व स्तर को प्राप्त करने का समय मिलेगा तो घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जाएगा । जैसाकि पहले कहा गया है एलएबी उद्योग के लिए क्षमता उपयोग का उच्च स्तर उसकी दीर्घकालीन वाणिज्यिक व्यवहार्यता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

(त) शुल्क अधिरोपण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए न्यूनतम 20% के रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण, दूसरे वर्ष में 15% तथा तीसरे वर्ष में 10% शुल्क के अधिरोपण का अनुरोध किया गया है । अनुरोध किए गए शुल्क के स्तर से घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी । प्रस्तावित अन्य उपायों सहित शुल्क के अधिरोपण से लागत में भी कमी आएगी ।

निर्यातक देशों की सरकारों तथा निर्यातकों के मत

12. सऊदी अरब की सरकार तथा गल्फ फराबी पेट्रोकेमिकल्स कं. लि. ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सार्वजनिक सुनवाई में हिस्सा लिया था । उनके लिखित अनुरोधों, सार्वजनिक सुनवाई के दौरान किए गए अनुरोधों तथा प्रत्युत्तरों का सारांश निम्नानुसार है :

13. गल्फ फराबी के मतानुसार इस सार्वजनिक सुनवाई के दौरान डीजीएसजी को इस बात का पर्याप्त साक्ष्य दिया गया था कि इस मामले में विशेष रूप से भारतीय तथा डब्ल्यूटीओ के रक्षोपाय नियमों द्वारा निर्धारित अत्यधिक उच्चस्तरीय मानकों को ध्यान में रखते हुए रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का कोई विशेष औचित्य नहीं बनता है ।

14. सऊदी अरब से आयातित एलएबी का एक प्रमुख हिस्सा निर्यातानुमुखी इकाई स्कीम के अंतर्गत आयात किया जा रहा है ।
15. याचिकाकर्ताओं ने आयातों में वृद्धि से संबंधित जो अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है, उसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है ।
16. जाँच अवधि के दौरान आयातों में हुई वृद्धि भारतीय उत्पादकों की निर्यात प्रधान कार्यनीति का परिणाम है ।
17. एलएबी के आयात कम कीमतों पर नहीं हो रहे हैं ।
18. याचिकाकर्ताओं को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है क्योंकि
 - क. उत्पादन का स्तर यथावत रहा है;
 - ख. वैश्वीकृत बाजार में याचिकाकर्ताओं का बाजार हिस्सा बहुत अधिक है;
 - ग. क्षमता उपयोग बहुत ऊँचे स्तर पर है;
 - घ. लाभ में गिरावट, यदि कोई है, का कारण बड़े हुए आयात नहीं हैं ।
19. क्षति, यदि कोई है, बड़े हुए आयातों के कारण नहीं हुई है ।
20. भारतीय एलएबी बाजार में आईओसी के प्रवेश से इस देश में बाजारी शक्तियों में आमूल परिवर्तन हुआ है ।
21. किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना नहीं हुई है क्योंकि मध्य-पूर्व क्षेत्र से भारत में एलएबी का प्रवाह पूर्व प्रत्याशित एवं पूर्वानुमेय था ।
22. निर्यात निष्पादन भारतीय उत्पादकों की सुविचारित कार्यनीति का परिणाम था जिसके द्वारा वे भारतीय बाजार और भारतीय प्रयोक्ताओं तथा उपभोक्ताओं की लागत पर वैश्विक बाजार में निर्यातों को अनुचित लाभ पहुँचाना चाहते थे ।
23. किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है ।
24. उपर्युक्त के आधार पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का कोई औचित्य नहीं है ।

25. वर्तमान संदर्भ में जबकि वैश्विक आर्थिक संकट के कारण रक्षोपाय अपनाए जाने का दबाव काफी बढ़ गया है, तब यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण ऐसा कोई उपाय न अपनाएँ जो डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत पूर्णतः उचित न हो।

26. कतर सरकार एसईईएफ लि., मेसईद तथा अन्य ने अपने लिखित अनुरोधों के माध्यम से निम्नलिखित अभिकथन प्रस्तुत किए हैं :-

क. भारत में एलएबी का आयात उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर किया जा रहा है जिन कीमतों पर विश्व के किसी भी अन्य देश को किया जाता है।

ख. भारत के एलएबी उत्पादक अपने उत्पादन के लगभग 30% का निर्यात लगभग समान अंतर्राष्ट्रीय कीमत और कभी-कभी उस कीमत से भी कम कीमत पर करते हैं जिस कीमत पर भारत में एलएबी का आयात होता है।

ग. 7.5% का सीमाशुल्क घरेलू उद्योग की सुरक्षा हेतु पर्याप्त है।

घ. रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से डिटर्जेंट उद्योग वैश्विक रूप से अप्रतिस्पर्धी बन जाएगा।

ड. एसईईएफ लि., कतर यूओपी की आधुनिकतम डेटल प्रक्रिया के प्रयोग द्वारा एलएबी का विनिर्माण करते हैं और डिटर्जेंट उद्योग द्वारा हमारे संयंत्रों से उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता को बरीयता दी जाती है। भारत में केवल आईओसी और निरमा इस प्रक्रिया द्वारा उत्पादन करते हैं।

च. मध्य-पूर्व के एलएबी आपूर्तिकर्ता भारत को एलएबी की आपूर्ति करके और भारतीय एलएबी विनिर्माताओं के लिए कच्ची सामग्री की आपूर्ति करके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय डिटर्जेंट उद्योग की सहायता कर रहे हैं।

छ. मध्य-पूर्व से एलएबी की आपूर्ति नियमित रही है अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

ज. आयातों में किसी प्रकार की कोई आकस्मिक तथा अत्यधिक वृद्धि नहीं हुई है जिससे गंभीर क्षति हुई हो।

झ. किसी प्रकार की गंभीर क्षति नहीं हुई है।

27. मै. हिन्दुस्तान यूनिवर्सिटी लि. ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान अपने लिखित अनुरोधों के जरिए निम्नलिखित मुद्दे प्रस्तुत किए हैं :

क. रक्षोपाय संबंधी कार्यवाही असाधारण स्थितियों में किया जाने वाला उपाय है और “ गंभीर क्षति ” के मानक अत्यधिक उच्च स्तर के होते हैं । रक्षोपाय शुल्क का सहारा केवल आपातकालीन स्थितियों में ही लिया जाना चाहिए ।

ख. “ हालिया ” शब्द से भूतलक्षी प्रभाव का विश्लेषण द्योतित होता है । इसका अर्थ प्राधिकरण के निर्णय से तुरंत पहले विद्यमान परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं है । उन्होंने यूएस-लाइन पाइप रक्षोपाय के मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल के निर्णय का हवाला दिया था । आयात में हुई वृद्धि आकस्मिक तथा अत्यधिक नहीं है । यह नाटकीय भी नहीं है । निर्यात हेतु उद्दिष्ट अंतिम उत्पादों के विनिर्माण के लिए आशयित आयातों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए । यदि इन आयातों को शामिल न किया जाए तो वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में आयात का हिस्सा क्रमशः 2.98% तथा 7.05% होगा ।

ग. घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति में कोई विशेष गिरावट नहीं आई है । रक्षोपाय शुल्क का अनुरोध करने वाली कम्पनियाँ वित्तीय रूप से सुदृढ़ हैं और बड़े आर्थिक समुदायों से संबंधित हैं ।

घ. घरेलू बिक्रियों का स्थान निर्यातों द्वारा लिया जा रहा है जो घरेलू बिक्री के 40% से अधिक हैं । बाजार हिस्से में गिरावट होने का दावा अत्यंत भ्रामक है क्योंकि वास्तव में बिक्री में बढ़ोत्तरी हो रही थी ।

ड. क्षमता उपयोग अत्यधिक है ।

च. रक्षोपाय का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं ने गोपनीय मानी गई सूचना का अगोपनीय सार प्रस्तुत नहीं किया है । इससे हितबद्ध पक्षकार सार्थक अनुरोध करने के अधिकार से वंचित हुए हैं । हितबद्ध पक्षकारों के पास लाभ के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

छ. कोई कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है। संयंत्रों के बंद होने का कारण निर्यात नहीं है। क्षति अत्यधिक उच्च कीमत के कारण हुई है। घरेलू उद्योग में बेशी आपूर्ति के कारण भी क्षति हुई है। घरेलू उद्योग फल फूल रहे हैं। पुनर्संरचना योजना के समुचित सारांश और अत्यधिक गोपनीयता का अभाव है।

ज. रक्षोपाय शुल्क जैसे व्यापार सुधार उपाय के प्रशासन में 'जनहित' पर विचार करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इस संबंध में यूनाइटेड फॉस्फोरस बनाम महानिदेशक रक्षोपाय, 2000(118) ईएलटी 326 (दिल्ली) के मामले को भी उद्धृत किया है।

झ. एलएबी और डिटर्जेंट कीमत के बीच घनिष्ठ संबंध है।

पूर्ववर्ती निवेदनों का सारांश:

ज. घरेलू उद्योग उपयोक्ताओं पर आवश्यकता से अधिक प्रभार लगा रहे हैं। एलएबी एक मध्यवर्ती उत्पाद है और यह डिटर्जेंट टिकिया और पाउडर के विनिर्माण की एक निविष्टि है और अंतिम उत्पाद की लागत में इसका योगदान लगभग 50% से 60% होता है। निविष्टि (एलएबी) की कीमतों में हुई किसी भी वृद्धि से अंतिम उत्पाद की लागत भी निःसंदेह बढ़ जाएगी।

ट. एलएबी की कीमत बढ़ गई है और कीमतों में हुई वृद्धि की परिणति डिटर्जेंटों की कीमतों में हुई आनुपातिक वृद्धि के रूप में हुई है और इसने लगभग 20 करोड़ भारतीय परिवारों को प्रभावित किया है क्योंकि डिटर्जेंट टिकिया और पाउडर का उपयोग प्रत्येक भारतीय परिवार में किया जाता है। इसके अलावा भारत के डिटर्जेंट उद्योग में हजारों छोटी-छोटी इकाइयां, लघु उद्योग और कुछेक मध्यम एवं बड़े विनिर्माता शामिल हैं। एलएबी उद्योग की तुलना में डिटर्जेंट उद्योग अत्यधिक श्रम गहन है। इनमें पाँच लाख से अधिक कामगार नियोजित हैं, जो केवल लगभग 500 कामगारों को रोजगार देने वाले एलएबी उद्योग की तुलना में काफी अधिक है। भारत में एलएबी के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर दिए जाने की स्थिति में अनुषंगी डिटर्जेंट उद्योग की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और इस प्रकार इस उद्योग में नियोजित लाखों कामगारों की आजीविका प्रभावित होगी।

ठ. घरेलू उद्योग द्वारा एलएबी के कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है। तथापि, कुल घरेलू खपत में घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट के साथ-साथ घरेलू उद्योग के निर्यात उत्पादन में समनुरूपी वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह है कि घरेलू उद्योग की बिक्री

पद्धति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है जिसका झुकाव निर्यात की तरफ अधिक है। कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता में निर्यातों का हिस्सा अत्यधिक उच्च है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि भारत में उत्पादित एलएबी को अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात बाजार की ओर मोड़ा जा रहा है। घरेलू उद्योग के घरेलू बाजार हिस्से की हानि, यदि कोई हो, के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है और यह घरेलू उद्योग को हुई किसी प्रकार की क्षति का संकेतक नहीं है।

उ. याचिकाकर्ता क्षमता उद्योग के अत्यधिक उच्च स्तर पर प्रचालन कर रहे हैं।

ड. माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आयातों के सबसे ताजा आंकड़ों के आधार पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति अथवा क्षति के खतरे का नियमित रूप से निर्धारण किया जाता रहा है।

ण. याचिकाकर्ता एलएबी के बढ़ते हुए आयातों तथा उनके द्वारा उठाई गई गंभीर क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध की पुष्टि करने में असमर्थ रहे हैं।

त. याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके संयंत्रों के बंद किए जाने संबंधी दावे भ्रामक हैं। तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लि० तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० दोनों ही बड़े पेट्रो-रसायन विनिर्माता हैं और संयंत्र के बंद किए जाने संबंधी सूचना का तात्पर्य सामान्य रख-रखाव तथा उन्नयन प्रयोजनों हेतु अथवा फीडस्टॉक की अनुपलब्धता के कारण अस्थायी रूप बंद किये जाने से है। याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावों के विपरीत, उनके संयंत्र भारत में एलएबी के आयातों में वृद्धि तथा एलएबी की बिक्री करने में उनकी असमर्थता के कारण नहीं परंतु सामान्य टूट-फूट की मरम्मत आदि जैसे अस्थायी कारणों से बंद किए गए थे। इसके विपरीत याचिकाकर्ता ने घरेलू बाजार तथा निर्यात बाजार दोनों में एलएबी के उत्पादन एवं बिक्री को जारी रखा है।

थ. एलएबी के उपयोक्ताओं को घरेलू स्रोतों से एलएबी की अधिप्राप्ति में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे एलएबी के उपयोक्ता वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने और आयातों के माध्यम से अपनी मांग को पूरा करने के विकल्प की तलाश करने के लिए बाध्य हो गए हैं। घरेलू तौर पर एलएबी की अधिप्राप्ति में कठिनाई इस कारण से और भी अधिक बढ़ गई है कि घरेलू उत्पादकों में घरेलू बिक्रियों के स्थान पर निर्यात करने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हो रही है।

द. घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में उपलब्ध कराए गए विवरणों की समीक्षा से यह प्रदर्शित होता है कि बढ़ते हुए आयातों को समायोजित करने के उनके प्रयास

बिल्कुल अपर्याप्त है और उनके इस दावे, कि उन्हें बढ़ते हुए आयातों के कारण क्षति हुई है, की असंगतता को और भी रेखांकित करते हैं।

घ. उपर्युक्त के आलोक में, भारत में एलएबी के बढ़ते आयातों के कारण एलएबी के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति का खतरा मौजूद नहीं है।

28. एडवांस होम एंड पर्सनल केयर लि, नई दिल्ली, एडवांस सर्फेक्टेन्ट्स इंडिया लि०, नई दिल्ली, ए.आर. स्टैंकैम प्रा.लि. कोलकाता, न्यू इंडिया डिटर्जेंट्स लि, नई दिल्ली, मै. फेना (प्रा.) लि०, नई दिल्ली, रोहित सर्फेक्टेन्ट्स (प्रा.) लि०, कानपुर, साईं सलफोनेट्स प्रा.लि. कोलकाता, शांतिनाथ डिटर्जेंट्स (प्रा.) लि०, कोलकाता, स्मॉल स्केल डिटर्जेंट्स एण्ड सोप मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, कोलकाता एवं स्टैंडर्ड सर्फेक्टेन्ट्स लि०, कानपुर ने लिखित निवेदन प्रस्तुत किए थे और सार्वजनिक सुनवाई में भी हिस्सा लिया था एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए थे। उनके द्वारा दिए गए तर्कों का सारांश निम्नानुसार है :-

क. जांच का प्रारंभ करना गैट 1994 के अनुच्छेद XIX का उल्लंघन है क्योंकि किसी अप्रत्याशित घटनाक्रम की स्थिति प्रदर्शित नहीं होती है।

ख. इस वृद्धि को पर्याप्ततः उल्लेखनीय, पर्याप्ततः उच्च अथवा पर्याप्ततः आकस्मिक नहीं माना जा सकता है। यद्यपि वर्ष 2006-07 की तुलना में वर्ष 2007-08 में आयातों में वृद्धि हुई थी तथापि ऐसी वृद्धि को हाल में हुई वृद्धि बिल्कुल नहीं माना जा सकता है विशेषकर तब जबकि जांच की शुरुआत दिसम्बर, 2008 में की गई थी।

ग. घरेलू उत्पादकों द्वारा सार्वजनिक सुनवाई के समय प्रस्तुत आंकड़े महानिदेशक द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों में दर्ज आंकड़ों से पूर्णतः भिन्न हैं।

घ. मामले से संबंधित मूलभूत आंकड़े भी उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। ऐसे आंकड़ों को डीजी रक्षोपाय द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के समान होगा।

ड. यह देखा जा सकता है कि उद्योग में आईओसीएल के प्रवेश के साथ, अन्य घरेलू उत्पादक काफी दबाव का सामना कर रहे हैं। अन्य तीन उत्पादकों के हिस्से में गिरावट आई है और आईओसीएल के हिस्से में वृद्धि हुई है।

च. घरेलू उत्पादकों को किसी प्रकार की 'गंभीर क्षति' नहीं हुई है।

छ. घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्धारित एलएबी की कीमतें हमेशा एक सी रही हैं। यहां तक कि कीमत संशोधन भी अनुक्रम में रहे हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू उत्पादक उच्च कीमतों में गिरावट के बावजूद अत्यधिक उच्च कीमतें प्रभारित करते रहे हैं।

ज. जनहित पर विचार नहीं किया गया है विशेष रूप से तब जबकि आवेदक बड़े निगम हैं जिनका व्यक्तिगत कारोबार डिटर्जेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के सभी सदस्यों के समग्र संचयी कारोबार से अधिक है।

झ. इन्फोड्राइव से प्राप्त आयात आंकड़े आईबीआईएस तथा डीजीसीआईएस के आंकड़ों से भिन्न हैं। यदि इन्फोड्राइव के आंकड़ों पर विचार किया जाता है तो आयातों में कम वृद्धि हुई है।

ञ. यदि आईओसी को भी घरेलू उद्योग का एक हिस्सा माना जाता है तो कुल बिक्रियाँ वर्ष 2006-07 में 307503 मी.टन, वर्ष 2007-08 में 320212 मी.टन तथा वर्ष 2008-09 में 290014 मी. टन की होंगी। इसी प्रकार आईओसी को शामिल करते हुए कुल उत्पादन वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 के लिए क्रमशः 459808 मी. टन, 471010 मी. टन तथा 412549 मी. टन होगा। यदि आयातों हेतु इन्फोड्राइव के आंकड़ों पर विचार किया जाता है और आर्थिक मानदण्डों में आईओसी के आंकड़ों को भी जोड़ा जाता है तो वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 के लिए आयात का हिस्सा क्रमशः 7%, 12% एवं 14% होगा।

ट. आयातों में वृद्धि के बावजूद वर्ष 2008-09 में लाभप्रदता में सुधार हुआ है।

ठ. जनहित साबित करने का उत्तरदायित्व घरेलू उद्योग पर है।

ड. पुनर्संरचना योजना व्यापक एवं व्यवहार्य नहीं है।

पूर्ववर्ती निवेदन:

ढ. आयात आंकड़े असंगत हैं और मामले की वर्तमान स्थिति को नहीं दर्शाते हैं। जांच दिसम्बर, 2008 में शुरू की गई थी। तथापि, याचिका में केवल वित्तीय वर्ष 2007-08 तक के ही आयात आंकड़े मौजूद हैं।

ण. घरेलू उत्पादकों के संयंत्र चल रहे हैं और इसलिए संयंत्रों के बंद होने के दावे असत्य हैं।

त. उत्पादन में कोई गिरावट नहीं हुई है ।

थ. बड़े औद्योगिक समूह, जो एलएबी का विनिर्माण करते हैं कि तुलना में एलएबी के अंतिम प्रयोक्ता मध्यम एवं लघु आकार के उद्यम हैं । एलएबी उत्पादक एक उत्पादक संघ की तरह कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपनी घरेलू कीमतों को अत्यधिक कृत्रिम रूप से उच्च स्तरों पर रखा है । सभी चार घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रभारित बिक्री कीमतें सदा ही एक क्रम में रहीं हैं । घरेलू बिक्री कीमतें सदा ही उन कीमतों से काफी अधिक रही है जिन कीमतों पर उनका निर्यात अन्य देशों को किया जाता है; आयात कीमतें उनकी घरेलू कीमतों एवं निर्यात कीमतों के बीच रही हैं ।

द. एलएबी के भारतीय अंतिम प्रयोक्ता, एलएबी के घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रभारित अत्यंत उच्च कीमतों का भुगतान करते रहे हैं और रक्षोपाय शुल्कों को लागू करने की मांग करते हुए वर्तमान याचिका केवल अत्यधिक लाभों का बचाव करने के लिए ही प्रस्तुत की गई है ।

ध. एलएबी पर पहले से ही 7.5% की दर से आधारभूत सीमाशुल्क लागू है । तैयार उपभोक्ता डिटर्जेंट उत्पादों पर, 10% का सबसे उच्च आयात शुल्क लगाया जाता है । अतः एलएबी पर रक्षोपाय शुल्कों को लागू करने से एक प्रतिशत शुल्क संरचना तैयार होगी जहां किसी मूलभूत कच्ची सामग्री पर लगाया गया सीमाशुल्क, तैयार उत्पादों पर लागू शुल्क से अधिक होगा ।

न. एलएबी की लागत में किसी वृद्धि से डिटर्जेंटों की कीमत पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा और तदनन्तर उसके परिणाम स्वरूप डिटर्जेंटों के उत्पादन एवं बिक्री में कमी आएगी । एलएबी के 4 विनिर्माताओं की तुलना में भारत में डिटर्जेंट के 4000 से अधिक विनिर्माता हैं । एलएबी उत्पादकों द्वारा नियोजित 500 व्यक्तियों की तुलना में वे 500,000 व्यक्तियों को नियोजित करते हैं । अतः रक्षोपाय न लागू करने की स्थिति की तुलना में रक्षोपाय लागू करने से बड़ी संख्या में कर्मचारियों के रोजगार अवसर खतरे में पड़ जाएंगे ।

प. अनंतिम रक्षोपाय लागू किए जाने के कारण वर्तमान मामले में किसी प्रकार की 'अप्रत्याशित परिस्थितियां' मौजूद नहीं हैं ।

फ. आगे यह भी तर्क दिया गया है कि गंभीर क्षति के निर्धारण हेतु अनुच्छेद 4.2(क) के तहत 'समी संगत कारकों' पर विचार करना महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है ।

ब. आगे एलएबी की आयात कीमतें अधिकांशतः भारतीय एलएबी विनिर्माताओं की निर्यात कीमत से उच्च होती हैं। यह देखा जा सकता है कि कुल घरेलू उत्पादन का कम से कम 30% घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात किया जा रहा है। यह निर्धारित करना अवास्तविक है कि यदि घरेलू उद्योग, घरेलू बाजार में हानि उठा रहा है तो वह कम कीमतों पर इतनी अधिक मात्राओं का निर्यात करेगा।

भ. आयातकों के पास उपलब्ध बाजार आसूचना के अनुसार औसत निवल बिक्री वसूली तथा घरेलू उद्योग का मार्जिन - 5% से 23% के बीच रहता है।

म. 'आपात परिस्थिति' का कोई मामला मौजूद नहीं है।

य. उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि अनंतिम अथवा अंतिम उपायों को लागू करना 'जनहित' के विरुद्ध होगा और एओएस के अनुच्छेद 3.1 के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों (आयातकों, निर्यातकों, उत्पादकों इत्यादि) हेतु उनके मतों को प्रस्तुत करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन करना अथवा अन्य समुचित माध्यम उपलब्ध करवाना जांचकर्ता प्राधिकारियों का दायित्व है।

कक. इसके अलावा, दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 की जांच शुरुआत संबंधी सूचना में किसी अप्रत्याशित घटनाक्रम का उल्लेख नहीं है, जो भारत द्वारा डब्ल्यूटीओ के समक्ष की गई वचनबद्धता के परिणामरूप घटित हुआ हो।

खख. मध्यपूर्व के चार निर्यातक देशों में क्षमतावर्धन मात्र 15000 टन अथवा मात्र 4.6% है, अतः घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का कोई खतरा उत्पन्न नहीं होता, जिसके अभाव में प्रारंभिक रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे नगण्य क्षमता वर्धन, व्यवसाय में आमतौर पर किए जाते हैं और उपर्युक्त परिवर्तनों को 'घटनाक्रम' तो कहा जा सकता है, परंतु 'अप्रत्याशित घटनाक्रम' कदापि नहीं कहा जा सकता, जो भारत द्वारा की गई वचनबद्धता के परिणामस्वरूप घटित हुआ हो।

गग. कच्चे माल में तुलनात्मक लाभ कीमतों तथा मात्रा के रूप में प्रदर्शित होता है जिसके लिए कोई रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं किया जा सकता। मध्यपूर्व में तेल उत्पादन पिछले अनेक दशकों से एक व्यापक रूप से ज्ञात कारक है। रक्षोपाय सहित व्यापार सुधार के उपायों का उद्देश्य कम्पनियों को अपनी राष्ट्रीय सरकारों से संरक्षण की मांग करते हुए 'असामान्य लाभ' अर्जित करने की अनुमति देना नहीं है।

घघ. ऐसी कोई विश्वसनीय पुनः संरचना योजना भी नहीं है, जिसे घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।

ड.ड. यह निर्विवाद तथ्य है कि एलएबी की उत्पादन लागत पूर्णतः अपरिष्कृत तेल की कीमतों पर आधारित होती है, परंतु घरेलू कीमतों में अपरिष्कृत तेल कीमतों में गिरावट को नहीं दर्शाया गया है।

चच. जांच शुरूआत गैट 1994 के अनुच्छेद XIX का उल्लंघन है, क्योंकि कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम हुआ प्रतीत नहीं होता। इसके अलावा गैट 1994 के अनुच्छेद XIX के अनुसार रक्षोपाय शुल्क तभी अधिरोपित किया जा सकता है, जब अप्रत्याशित घटनाक्रम के परिणामस्वरूप आयातों में एकाएक वृद्धि हुई हो अथवा गैट के अन्तर्गत किसी संविदाकारी पक्षकार देश द्वारा की गई वचनबद्धता के परिणामस्वरूप ऐसा हुआ हो, जिसके कारण उस संविदाकारी पक्षकार देश के भू-भाग में घरेलू उत्पादकों को समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों के कारण क्षति हुई हो अथवा गंभीर क्षति का खतरा उत्पन्न हुआ हो।

छछ. मध्यपूर्व के चार निर्यातक देशों अर्थात् ईरान, कतर, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात में क्षमतावर्धन महज 15,000 टन अथवा 4.6% है।

जज. याचिका में उल्लिखित मानदण्ड 'गंभीर क्षति' अथवा 'गंभीर क्षति के खतरे' का समर्थन नहीं करते।

झझ. इसके अलावा, लागत में प्रस्तावित कमी, लागू शुल्कों के स्तर अथवा उनके द्वारा निवेदित शुल्क के स्तर के बीच कोई सह संबंध प्रतीत नहीं होता।

अन्य निवेदन:

29. जिन हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में भाग नहीं लिया था, उनके द्वारा किए गए निवेदनों का सारांश निम्नानुसार है :-

क. एलएबी की कीमत में वृद्धि हुई है और कीमतों में ऐसी वृद्धि के कारण डिटर्जेंटों की कीमतों में भी अनुपातिक वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से लगभग 20 करोड़ भारतीय परिवार प्रभावित हुए हैं क्योंकि डिटर्जेंट पाऊडर और टिकिया का उपयोग प्रत्येक भारतीय परिवार में किया जाता है। इसके अलावा भारत के डिटर्जेंट उद्योग में हजारों अति लघु यूनितें, लघु उद्योग यूनितें और कुछेक मध्यम और वृहद विनिर्माता शामिल हैं। एलएबी उद्योग की तुलना में डिटर्जेंट उद्योग अत्यंत श्रमगहन है। इसमें लगभग पांच लाख से अधिक कामगार नियोजित हैं और यह संख्या एलएबी उद्योग, जिसमें केवल 500 कामगार

नियोजित है, की तुलना में बहुत अधिक है । भारत में एलएबी के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किए जाने की स्थिति में अनुषंगी डिटर्जेंट उद्योग की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार इस उद्योग में नियोजित लाखों कामगारों की आजीविका प्रभावित होगी ।

ख. घरेलू उद्योग के चार संघटक बहु उत्पाद, वृहद विनिर्माण कम्पनियां हैं । एलएबी का विनिर्माण एवं उत्पादन इन कम्पनियों के समग्र व्यवसाय का अत्यंत अल्प प्रतिशत है । याचिकाकर्ताओं के वृहद आकार और उनकी उत्पाद रूपरेखा में एलएबी की अपेक्षाकृत कम उपस्थिति को देखते हुए, यह असंभावित है कि केवल एलएबी के आयातों में वृद्धि की वजह से उन्हें 'अत्यधिक समग्र: व्यवधान' उत्पन्न होगा ।

ग. कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू बिक्री के स्थान पर निर्यात किया जा रहा है और भारत एलएबी का निवल निर्यातक है ।

घ. भारतीय उद्योग निर्यातोन्मुख दृष्टिकोण अपना रहे हैं ।

ङ. याचिकाकर्ता अत्यधिक क्षमता उपयोग पर प्रचालन कर रहे हैं ।

च. संयंत्रों को नेमी अनुरक्षण कार्य तथा व्यावसायिक निर्णय के कारण बंद किया गया है, न कि आयात के कारण ।

छ. क्षति घरेलू बाजार में अत्यधिक आपूर्ति के कारण हुई है ।

ज. घरेलू उद्योग फल-फूल रहा है क्योंकि एलएबी उनके व्यवसाय का अत्यल्प अनुपात है ।

झ. पुनः संरचना योजना पर्याप्त नहीं है ।

जनहित रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित न किए जाने के पक्ष में है क्योंकि अंतिम प्रयोक्ताओं की संख्या बहुत बड़ी है जिसमें काफी संख्या में लोग नियोजित हैं, जो डिटर्जेंट का विनिर्माण करते हैं ।

ट. घरेलू उद्योग अंतिम प्रयोक्ताओं को पर्याप्त एलएबी उपलब्ध कराने में असमर्थ है ।

ठ. कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है और कोई रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए।

जांच एवं जांच परिणाम:

30. मैंने मामले के रिकार्ड तथा घरेलू उत्पादकों, प्रयोक्ताओं/आयातकों, निर्यातकों और निर्यातक सरकार द्वारा प्रस्तुत उत्तरों की सावधानीपूर्वक पड़ताल की है। विभिन्न पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों और उनसे उठे मुद्दों का विवेचन निम्नलिखित जांच परिणाम में यथास्थान किया गया है।

विधि तथा सूचना का स्रोत:

31. आयात आंकड़ों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2006-07 तक डीजीसीआईएस आंकड़ों तथा परवर्ती अवधि हेतु आईबीआईएस आंकड़ों को विश्वसनीय माना गया है। सूचना का सौदेवार ब्यौरा सार्वजनिक फाइल में रखा गया है। भारत के सभी विनिर्माताओं से संबंधित अन्य आर्थिक मानदण्डों संबंधी सूचना आवेदकों से प्राप्त की गई है। यदि किसी अन्य सूचना को प्रयुक्त किया गया है, तो सूचना के साथ उसके स्रोत का उल्लेख भी किया गया है।

जांचाधीन उत्पाद

32. जांचाधीन उत्पाद "ऑल लीनीयर अल्काइल बेंज़ीन, मिक्स्ट अल्काइल बेंज़ीन" है। यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची 1 के उपशीर्ष सं. 38170011, आई टी सी के उपशीर्ष सं. 38170011 तथा एच एस एन की उप शीर्ष सं. 38170011 के तहत वर्गीकृत है। जांच की विषय वस्तु केवल मिक्स्ट अल्काइल बेंज़ीन और लीनीयर अल्काइल बेंज़ीर है न कि मिक्स्ट अल्काइल नेप्थालीन्स। उपर्युक्त उत्पाद को वाणिज्यिक बाजार की भाषा में सामान्यतः "लीनीयर अल्काइल बेंज़ीन" (संक्षिप्त में "एल ए बी") के नाम से जाना जाता है।

33. घरेलू उद्योग लीनीयर अल्काइल बेंज़ीन के उत्पादन हेतु कच्ची समग्री के रूप में केरोसीन (निस्सारित - सी 10 - सी 13 पैराफिन्स) एवं बेंज़ीन का उपयोग करता है। सी 10 - सी 13 पैराफिन्स को फीडस्टॉक केरोसीन से हाइड्रोबोन मोलेक्स प्रक्रिया द्वारा निस्सारित किया जाता है। इन पैराफिनों को उच्च ताप पर चयनात्मक डिहाइड्रोजेनेशन द्वारा उनके ओलेफिन्स में परिवर्तित किया जाता है। सी 10 - सी 13 ओलेफिनों को एल्किलीकृत करके बेंज़ीन बनाया जाता है जिससे लीनीयर अल्काइल

बेंजीन बनता है। सी 10 - सी 13 लीनीयर ओलेफिन्स से उत्पादित लीनीयर एल्किलबेंजीन उपयोगी डिटर्जेंट मध्यवर्ती होते हैं और उन्हें सरलता से सल्फोनेट करके लीनीयर एल्किलबेंजीन सल्फोनेट्स बनाया जा सकता है। ये यौगिक घरेलू डिटर्जेंट के "सक्रिय" घटक होते हैं। वे सर्फेस एक्टिव यौगिक (सर्फेक्टेन्ट्स) होते हैं जिन्हें विभिन्न विनिर्मितियों (अक्सर अकार्बनिक साल्ट्स) के साथ संयोजित करके डिटर्जेंट बनाया जाता है। संक्षिप्त में एल ए बी का उपयोग डिटर्जेंट उद्योगों द्वारा एक महत्वपूर्ण निविष्टि के रूप में किया जाता है।

34. जहां तक जांचाधीन उत्पाद का संबंध है, मैसर्स गल्फ फराबी पेट्रोकेमिकल्स कं.लि. ने दावा किया है कि उनके द्वारा आपूर्त उत्पाद भारत में घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू तौर पर बेचे जाने वाले उत्पाद से भिन्न है। गल्फ फराब एलएबी में घरेलू उत्पाद की तुलना में भिन्न कार्बन श्रृंखला वितरण पैटर्न होता है और इसका आण्विक भार घरेलू तौर पर विनिर्मित उत्पाद से कम है। गल्फ फराबी से आयातित एलएबी का डिटर्जेंट निष्पादन बेहतर है। अतः ये एक समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पाद नहीं हैं।

35. इस मुद्दे की जांच की गई है। लीनीयर एल्काइल बेंजीन की उत्पादन प्रक्रिया तथा विनिर्माण संयंत्र का डिजाइन इस उत्पाद की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं को कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है। मैसर्स गल्फ फराबी द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार आयातित एलएबी तथा घरेलू एलएबी का रंगरूप (अर्थात् स्पष्ट रंगहीन द्रव), ब्रोमीन इण्डेक्स, पैराफीन की मात्रा, 2-फिनाइल एल्केन्स, सामान्य एलएबी तथा नमी की मात्रा एक समान होती है। तथापि भारतीय एलएबी का औसत आण्विक भार 235-239 के बीच और गल्फ फराबी का औसत आण्विक भार 238-242 के बीच होता है। गुणवत्ता के संबंध में दावा किया गया यह अंतर इतना न्यून है कि इसका उनकी प्रतिस्थापनीयता और प्रतिस्पर्धात्मक होने की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वयं हितवद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि एलएबी की कीमतें तुलनीय हैं और उनमें कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है। उपर्युक्त के मद्देनजर यह पाया गया कि आयातित एलएबी तथा घरेलू तौर पर उत्पादित एलएबी में कुछेक मानदण्डों में न्यून अन्तर को छोड़कर उनकी रासायनिक और भौतिक विशेषताओं में कोई अन्तर नहीं है। तथापि मानदण्ड में अन्तर इतना अधिक नहीं है जिससे दोनों उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता भी प्रभावित होती हो। दोनों उत्पादों में एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की क्षमता मौजूद है और उनका इस प्रकार से उपयोग किया भी जा रहा है। अतः आयातित उत्पाद घरेलू उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पाद के "समान एवं प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी" उत्पाद है। अतः जांचाधीन उत्पाद एलएबी है, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है।

घरेलू उद्योग

36. वर्तमान जांच रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लि०, मुम्बई, तमिलनाडु पेट्रोप्रॉडक्ट्स लि० चेन्नै, निरमा लि०, अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर की गई है। मेसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली ने आवेदन का समर्थन किया है। इन कम्पनियों के हिस्से का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

तालिका-1

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
कम्पनी	हिस्सा	हिस्सा	हिस्सा	हिस्सा
इंडियन ऑयल	11%	24%	26%	28%
निरमा	26%	21%	19%	19%
रिलायंस	41%	38%	36%	36%
टीपीएल	22%	17%	19%	17%
कुल	100%	100%	100%	100%

37. इंडियन ऑयल, जो जाँच का समर्थन कर रहा है, को छोड़कर आवेदकों को हिस्सा वर्ष 2007-08 के दौरान 72%, रहा है और आवेदकों के साथ इंडियन ऑयल को मिलाकर विचार किए जाने पर उनका हिस्सा 100% रहा है। आवेदकों (इंडियन ऑयल को छोड़कर) को घरेलू उद्योग माने जाने के संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया गया है। तदनुसार, मै० रिलायंस इंडस्ट्रीज मुम्बई, तमिलनाडु पेट्रोप्रॉडक्ट्स लि०, चेन्नई, निरमा लि० अहमदाबाद के एलएबी व्यवसाय, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख की उप धारा (6) के खण्ड (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग हैं।

38. मुख्य रूप से केवल घरेलू उद्योग के संबंध में आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने तथा भारत में अंतर इकाई परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए कुछ स्थानों पर आईओसी के आँकड़ों का भी विश्लेषण किया गया है। तथापि, आयातों के बाजार हिस्से का विश्लेषण करने के लिए सम्पूर्ण आँकड़ों अर्थात् आईओसी सहित सभी के आँकड़ों का प्रयोग किया गया है।

जांच की अवधि:

39. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं निर्धारण) नियम 1997, रक्षोपाय करार और गैट के संगत अनुच्छेद XIX में इस आशय की विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है कि जांच अवधि क्या होनी चाहिए। तथापि, अर्जेंटीना फुटवियर पर पैनल की रिपोर्ट में एवं अर्जेंटीना पर अपीलीय

निकाय की रिपोर्ट में जांच अवधि के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

'अर्जेंटना-फुटबियर के आयातों पर रक्षोपाय : पैनल की रिपोर्ट'

8.216 जहाँ तक जाँच में घरेलू उद्योग की स्थिति में परिवर्तन के विश्लेषण में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक की गई तुलनाओं पर लगभग पूर्ण भरोसा किए जाने का संबंध है, हमारी भी वही चिंता है जैसी कि "संवर्धित आयातों" के विश्लेषण के बारे में ऊपर नोट किया गया है। यहाँ हम इस बात को खासतौर पर नोट करते हैं कि यदि मध्यवर्ती रूझानों पर क्रमबद्ध ढंग से विचार नहीं किया जाता है और उनका विश्लेषण नहीं किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी 'समस्त संगत कारकों' का विश्लेषण करने के बारे में अनुच्छेद 4.2(क) की अपेक्षा को पूरा नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा घरेलू उद्योग की स्थिति का पूर्णरूप से आकलन नहीं होता है। उदाहरणार्थ, ऐसी किसी उद्योग की स्थिति, जिसका उत्पादन एक वर्ष में काफी कम हो जाता है परंतु उसके बाद उसमें लगातार सुधार होता है यद्यपि कुछ स्तर तक यह शुरूआती स्तर से कुछ कम रहता है तो यह स्थिति तर्कसंगत ढंग से ऐसे किसी उद्योग की स्थिति से अलग होगी जिसके उत्पादन में विस्तारित अवधि के दौरान लगातार गिरावट आई है। एक छोर से दूसरे छोर तक का विश्लेषण दोनों मामलों में एक समान होना चाहिए जबकि वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों एवं रूझानों पर विचार करने से पूर्णतः विपरीत निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

8.217 हमारा मानना है कि विभिन्न क्षतिकारकों में जांच अवधि के दौरान परिवर्तनों पर विचार करना इस बात के निर्धारण हेतु अनिवार्य है कि क्या किसी उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या गंभीर क्षति होने का आसन्नवर्ती खतरा उत्पन्न हो गया है। मध्यवर्ती रूझानों पर विचार किए बिना एक छोर से दूसरे छोर तक की तुलना से अपेक्षानुसार समस्त संगत कारकों का पूर्ण मूल्यांकन प्रदान करने की संभावना नहीं है।

अपीलीय निकाय की रिपोर्ट

नोट 130.

पैनल ने पैनल रिपोर्ट के पैरा 8.166 की पद टिप्पणी 530 में यह स्वीकार किया है कि वर्तमान काल का उपयोग किया जा रहा है जिसमें यह उल्लेख है कि 'यह प्रतीत होगा कि जांच अवधि का शुरूआती बिन्दु कोई भी हो उसे हाल की निकटतम अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए' (जोर दिया गया)। यहाँ हम पैनल से सहमत नहीं हैं। हमारा मानना है कि संगत जांच अवधि हाल की निकटतम अवधि में समाप्त नहीं होनी चाहिए अपितु उसे हाल की अवधि होनी चाहिए।

40. उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि न तो खोपाय करार और न ही डब्ल्यूटीओ के संगत प्रावधानों में जाँच अवधि की विशिष्ट परिभाषा या व्याख्या निहित है। अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह पाँच परिणाम दिया गया है कि संगत जाँच अवधि हाल की निकटतम अवधि में समाप्त नहीं होनी चाहिए; जाँच अवधि हाल की अवधि होनी चाहिए।

41. वर्तमान मामले में जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना दिनांक 19.12.2008 को जारी की गई थी जिसमें मुख्य रूप से वर्ष 2007-08 तक के आँकड़े शामिल थे। प्रारंभिक जाँच परिणाम दिनांक 30.01.2009 को जारी किए गए थे जिसमें जाँच की प्रक्रिया के दौरान 2008-09 की पश्चवर्ती अवधि हेतु संग्रहीत आँकड़ों पर भी विचार किया गया था। चूंकि सार्वजनिक सुनवाई 23 जुलाई, 2009 को आयोजित की गई थी, अतः केवल 2007-08 तक की सूचना हाल की अवधि की नहीं थी। अन्य शब्दों में जब वित्त वर्ष 2008-09 के लिए आँकड़े उपलब्ध हैं तो उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है। अतः विश्लेषण के लिए ऐसी सूचना का प्रयोग जाँच के हित में है।

42. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने विरोध किया है कि नई सूचना को जोड़ने का तात्पर्य इस चरण में नए साक्ष्य जोड़ना है। इस संबंध में यह नोट किया गया है कि खोपाय जाँच प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया या अपीलीय प्रक्रिया से अलग होती है। खोपाय जाँच के दौरान नए तथ्य तथा साक्ष्य सामने आते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है। यदि केवल आवेदन में उल्लिखित तथ्यों पर विचार किया जाता है तो जाँच, जिसका प्रयोजन संगत सूचना को सामने लाना और बाजार परिस्थितियों का विश्लेषण करना होता है, निरर्थक हो जाएगी। अतः यह आवश्यक है कि जाँच के दौरान प्रकाश में आए सभी तथ्यों पर विचार किया जाए। तथापि, खोपाय शुल्क नियम के नियम 6 में यथा परिकल्पित प्राकृतिक न्याय की अपेक्षा को भी पूरा किया जाना आवश्यक होता है। अतः नए तथ्य, यदि वे गोपनीय न हों तो उन्हें सार्वजनिक फाइल में रखकर हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान मामले में समस्त संगत एवं अगोपनीय सूचना सार्वजनिक फाइल में रखी गई है और हालिया सूचना सहित समस्त सूचना पर विचार किया जा रहा है।

43. मौसम संबंधी अंतर, यदि कोई हो, को निष्प्रभावी करने के लिए पर्याप्त: लम्बे नमूने अर्थात् वित्त वर्ष 2005-06 से 2008-09 के वार्षिक आँकड़ों पर विचार किया गया है।

क्या निर्यातों में वृद्धि हुई है ?

44. **ऑकड़ों का स्रोत:** आयात ऑकड़ों का स्रोत डीजीसीआईएस और आईबीआईएस हैं। वर्ष 2006-07 तक के वार्षिक आयात ऑकड़ों के लिए डीजीसीआईएस के ऑकड़ों पर विश्वास किया गया है। वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 की अवधि के लिए सौदे-वार आयात ऑकड़ें आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। उन ऑकड़ों को सार्वजनिक फाइल में रख कर हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराया गया है। ऑकड़ों के सही होने के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है। तथापि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने विरोध किया है कि सार्वजनिक फाइल में रखे गए ऑकड़ों के स्रोत के गलत होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना किसी अन्य स्रोत द्वारा भिन्न आयात ऑकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वस्तुतः यह देखा गया है कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आईबीआईएस के ऑकड़ों का संदर्भ लिया है। अतः जब तक कि सिद्ध न किया जाए, आयातों से संबंधित ऑकड़ों के स्रोत को अविश्वसनीय नहीं जाना जा सकता है। अतः आयात विश्लेषण के प्रयोजनार्थ आईबीआईएस के ऑकड़ों का प्रयोग किया जा रहा है।

45. **सांविधिक संरचना:** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख में उन परिस्थितियों में रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का प्रावधान है जब किसी वस्तु का भारत में ऐसी संवर्धित मात्रा और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जा रहा हो जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही हो अथवा होने का खतरा हो।¹ 'संवर्धित मात्रा' शब्द के तात्पर्य पर अर्जेंटीना फुटबियर मामले में पैनल रिपोर्ट तथा अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में चर्चा की गई है। इन रिपोर्टों में यह माना गया है कि 'संवर्धित मात्रा' आयात में कोई भी वृद्धि नहीं हो सकती है। ऐसी वृद्धि हालिया और अचानक होनी चाहिए।² यह भी माना गया है कि आयात में वृद्धि से 'गंभीर क्षति' होने अथवा उसका खतरा उत्पन्न होने के लिए उसे मात्रा एवं गुणवत्तात्मक दोनों रूपों में पर्याप्त रूप से हालिया, अचानक, तीव्र और अत्यधिक होना आवश्यक है। आयात में वृद्धि से 'गंभीर क्षति' होने

¹ 8 ख- रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ : यदि केन्द्रीय सरकार यथोचित जाँच के बाद संतुष्ट हो कि किसी वस्तु का भारत में ऐसी संवर्धित मात्रा और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जा रहा है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही हो अथवा होने का खतरा है तो वह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क लगा सकती है।

² एबीआर अर्जेंटीना फुटबियर मामलों का पैरा 130

..... तथापि हम इस बात पर पैनल से सहमत हैं कि आयातों की 'संवर्धित मात्रा' कोई भी वृद्धि नहीं हो सकती है, तथापि हम इस बात पर पैनल से सहमत नहीं हैं कि पंचवर्षीय ऐतिहासिक अवधि में आयातों की प्रवृत्ति की जाँच करना उचित है। हमारे विचार में रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 और गेट 1994 के अनुच्छेद XIX:1 (क) दोनों में 'आयात की जा रही है' शब्दों में वर्तमान काल का प्रयोग यह दर्शाता है कि सक्षम प्राधिकारियों के लिए हाल के आयातों की जाँच करना आवश्यक है न कि पिछले पाँच वर्षों या फिर कई वर्षों की किसी भी अन्य अवधि के दौरान आयातों में प्रवृत्ति की जाँच करना।² हमारे विचार से 'आयात की जा रही है' शब्दावली का तात्पर्य यह है कि आयातों की में वृद्धि अकस्मात् एवं हालिया होगी।

अथवा उसका खतरा उत्पन्न होने के लिए उसे मात्रा एवं गुणवत्तात्मक दोनों रूपों में पर्याप्त रूप से हालिया, अचानक, तीव्र और अत्यधिक होना आवश्यक है।³

46. तथ्यों की जाँच: नीचे दी गई तालिका एलएबी से संबंधित आयात सांख्यिकी दर्शाती है।

तालिका: 2

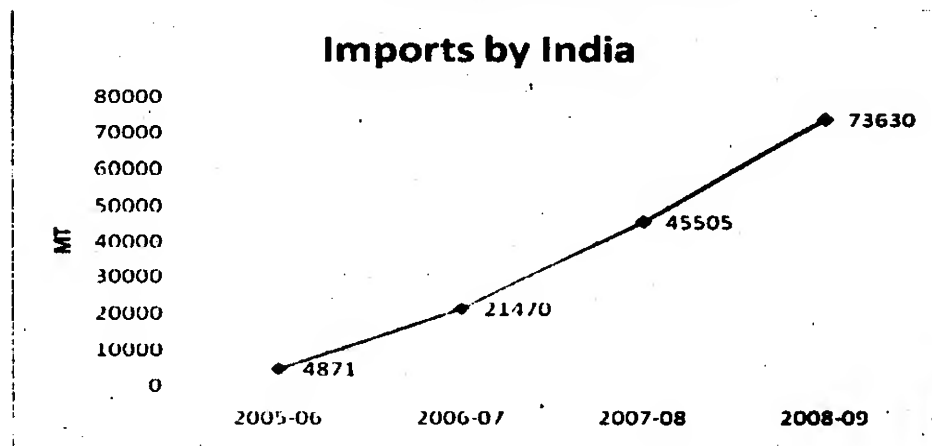
वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
आयात (मी.टन)	4871	21470	45505	73630
आयात का बाजार हिस्सा (%)	1.73%	7.22%	13.91%	21.16%

47. वर्ष 2008-09 में एलएबी का कुल आयात 73,630 मी.टन रहा है जिसमें पिछले वर्ष में हुए 45,505 मी.टन के आयात की तुलना में समग्र रूप से 28,125 मी.टन तथा प्रतिशत के रूप में 61.8% वृद्धि प्रदर्शित होती है। वर्ष 2005-06 को छोड़कर प्रत्येक वर्ष आयात में सतत वृद्धि हुई है।

48. कुल बाजार आकार में आयात का हिस्सा वर्ष 2005-06 में 1.73%, वर्ष 2006-07 में 7.22% तथा वर्ष 2007-08 में 13.91% से बढ़कर 21.16% हो गया है।

49. नीचे दिया गया ग्राफ 1 आयातों की प्रवृत्ति दर्शाता है। यह देखा गया है कि वर्ष 2006-07 में आयातों में वृद्धि की गति धीमी रही है। आयातों में वृद्धि में कोई अप्रत्याशितता नहीं है।

भारत द्वारा किए गए आयात



³ एबीआर अर्जेंटीना फुटबियर मामले का पैरा 131

..... हमारे विचार से इस बात का निर्धारण कि "ऐसी संवर्धित मात्रा में" आयातों की अपेक्षा पूरी हुई है, केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण नहीं है। दूसरे शब्दों में किसी भी जाँच के लिए केवल यह दर्शाना पर्याप्त नहीं है कि इस वर्ष उत्पाद का आयात पिछले वर्ष या पाँच वर्ष पहले की तुलना में अधिक रहा है। पुनश्च आयात की मात्रा में कोई भी वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी। रक्षोपाय लागू करने के लिए इस अपेक्षा को पूरा करने हेतु "ऐसी संवर्धित मात्रा" होनी चाहिए जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो अथवा होने का खतरा उत्पन्न हो। और हमारे विचार से रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 2.1 और गैट 1994 के अनुच्छेद XIX: 1(क) दोनों में इस भाषा से यह अपेक्षित है कि आयात में वृद्धि से "गंभीर क्षति" होने अथवा उसका खतरा उत्पन्न होने के लिए उसे मात्रा एवं गुणवत्तात्मक दोनों रूपों में पर्याप्त रूप से हालिया, अचानक, तीव्र और अत्यधिक होना आवश्यक है।

50. अतः, यह देखा गया है कि गणितीय रूप से आयातों में वृद्धि हुई है परंतु उसमें 'संवर्धित मात्रा' की विशेषता का अभाव है, जो उस संदर्भ में पूरा करने के लिए मौजूद होनी चाहिए जिस संदर्भ में संविधि में 'संवर्धित मात्रा' तथा 'ऐसी संवर्धित मात्रा में' शब्दों का प्रयोग किया गया है।

किन परिस्थितियों में आयात किए जा रहे हैं ?

51. निम्नलिखित तालिका में रूपए/मी.टन में आयातों का मूल्य दिया गया है। निम्नलिखित तालिका में संगत सांख्यिकी दर्शाई गई है।

तालिका 3

वर्ष (इकाई)	आयातों का सीआईएफ मूल्य/मी. टन रूपए
2005-06	47504
2006-07	53523
2007-08	55981
2008-09	70132

52. सीआईएफ मूल्य में वर्ष 2008-09 में 25.28% और 2007-08 में 4.6% वृद्धि हुई। पिछले वर्षों में आयातों के सीआईएफ मूल्य में सतत वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। अतः बढ़ी हुई कीमतों पर आयात हो रहे हैं।

**गंभीर क्षति एवं उसके कारणः
सांविधिक ढाँचा**

53. 'गंभीर क्षति' का तात्पर्य ऐसी क्षति से है जिसके कारण घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र विकृति आई है;⁴

54. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 4.2 (क) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क का अभिज्ञान एवं निर्धारण) नियम 1997 के नियम 8 में तकनीकी रूप से यह अपेक्षित है कि गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के निर्धारण हेतु कुछेक सूचीबद्ध कारकों तथा अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तथापि, इन उपबंधों में उस बात को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है कि ऐसे किसी मूल्यांकन से क्या प्रदर्शित होना चाहिए। इस प्रकार का कोई मूल्यांकन किसी मामला विशेष के तथ्यों और संबंधित घरेलू उद्योग की स्थिति पर निर्भर रहते हुए अलग-अलग मामलों में अलग-अलग

⁴ सी.शु. टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख (6) (ग)

उद्योगों के लिए अलग-अलग होगा। प्रत्येक सूचीबद्ध कारक के मूल्यांकन में यह प्रदर्शित करना अनिवार्य नहीं है कि ऐसे प्रत्येक कारक में 'गिरावट' आ रही है। उदाहरणार्थ एक मामले में बिक्री, रोजगार एवं उत्पादकता में अत्यधिक गिरावट हो सकती है जिससे 'घरेलू उद्योग की स्थिति में' 'पर्याप्त समग्र विकृति' का पता चलेगा और इस प्रकार गंभीर क्षति से संबंधित जांच परिणाम न्यायोचित ठहरेगा। दूसरे मामले में कुछेक ऐसे कारक हो सकते हैं जिनमें गिरावट नहीं आई है परंतु समग्र स्थिति से यह पता चलता है कि उद्योग में 'पर्याप्त समग्र विकृति' आई है। इस प्रकार समस्त सूचीबद्ध कारकों और किसी अन्य संगत कारक की तकनीकी जांच के अलावा यह अनिवार्य है कि उक्त उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन किया जाए।⁵

55. तदनुसार गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे का विश्लेषण करने में उन सभी कारकों पर विचार किया गया है जिनका उल्लेख नियमों में किया गया है और अन्य कारकों पर भी विचार किया गया है जो गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के निर्धारण हेतु संगत हैं। किसी भी कारक को असंगत नहीं माना गया है। संगत व्यापार चक्र एवं प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के संदर्भ में ऐसे समस्त संगत कारकों पर विचार किया गया है जो प्रभावित घरेलू उद्योग के लिए संगत हैं।

कारकों की जांच:

56. आयातों की वृद्धि की दर: नीचे दी गई तालिका पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में आयातों में वृद्धि की दर से संबंधित सूचना देती है। यह देखा गया है कि वर्ष 2007-08 में हुई 111.95% की वृद्धि और वर्ष 2006-07 में हुई 340.77% की वृद्धि (संबंधित पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में) की तुलना में वर्ष 2008-09 में आयातों में 61.80% की दर से वृद्धि हुई। उपर्युक्त ग्राफ 1⁶ यह दर्शाता है कि वर्ष 2006-07 से आयातों में वृद्धि धीमी तथा सतत रही है।

तालिका 4

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
आयात	4871	21470	45505	73630
आयातों की वृद्धि दर (पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में) %	-	340.77%	111.95%	61.80%

⁵ अर्जेंटीना फुटबलर मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के पैरा 139 पर आधारित।

⁶ संदर्भ पैरा 49

419265/04-5

57. संवर्धित आयातों द्वारा लिया गया घरेलू बाजार का हिस्सा : निम्नलिखित तालिका में भारतीय घरेलू बाजार में कुल भारतीय एलएबी उद्योग के हिस्से के संबंध में संगत आंकड़े दिए गए हैं ।

तालिका-5

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
बाजार का आकार (मी. टन)	280859	297394	327116	347959
भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा (%)	98.27	92.78	86.09	78.84

58. घरेलू बाजार में समस्त भारतीय उद्योगों का हिस्सा वर्ष 2005-06 में 98.27% था जो 2008-09 में घटकर 78.84% हो गया ।

59. बाजार हिस्से में कमी के कारणों का विश्लेषण किया गया था । वर्ष 2008-09 में वार्षिक क्षमता 81,022 मी. टन की थी और आयात 73,630 मी. टन के हुए थे । यह भी देखा गया है कि वर्ष 2007-08 की तुलना में 2008-09 के दौरान भारत के निर्यातों में 31,452 मी. टन की गिरावट आई जिससे भी वार्षिक क्षमता में कमी हुई । अतः बाजार हिस्से के मुख्य कारक आयातों से इतर कारक हैं ।

60. घरेलू बिक्री के स्तर में परिवर्तन : निम्नलिखित तालिका में “ घरेलू उद्योग ” और समस्त भारतीय उत्पादकों (आईओसी सहित) की संचयी घरेलू बिक्रियों से संबंधित संगत आंकड़े दिए गए हैं ।

तालिका 6

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
“ घरेलू उद्योग ” द्वारा बिक्री (मी. टन)	188942	185503	184212	169014
आईओसी सहित समस्त भारतीय उत्पादकों द्वारा संचयी बिक्री (मी. टन)	275988	275924	281611	274329

61. वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक “ घरेलू उद्योग ” की बिक्री में गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है ।

62. वर्ष 2007-08 की तुलना में 2008-09 में आईओसी सहित समस्त भारतीय उत्पादकों की बिक्री में 7282 मी. टन की गिरावट आई जो 2.58% बनती है । पिछले चार वर्षों के बिक्री के आंकड़ों से यह पता चलता है कि समस्त भारतीय उद्योगों की संचयी बिक्री 276963 मी. टन के औसत के (+/-)1.3% के बैंड में रही थी ।

63. **उत्पादन :** निम्नलिखित तालिका में “ घरेलू उद्योग ” आईओसी सहित समस्त भारतीय उत्पादकों के संचयी घरेलू उत्पादन से संबंधित संगत आंकड़े दिए गए हैं ।

तालिका 7

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
“ घरेलू उद्योग ” द्वारा उत्पादन (मी. टन)	356554	337808	338010	286549
आईओसी सहित समस्त भारतीय उत्पादकों द्वारा संचयी उत्पादन (मी. टन)	467985	459082	470331	416316

64. वर्ष 2007-08 की तुलना में 2008-09 में “ घरेलू उद्योग ” के कुल उत्पादन में 51461 मी. टन की गिरावट आई ।

65. भारतीय एलएबी विनिर्माताओं की अंतरइकाई गतिशीलता और समस्त घरेलू उत्पादकों के समग्र परिदृश्य का विश्लेषण करने के लिए समस्त भारतीय घरेलू उत्पादकों के उत्पादन के आंकड़ों का भी विश्लेषण किया गया है । समस्त घरेलू उत्पादकों (आईओसी सहित) के कुल उत्पादन के विश्लेषण से यह पता चलता है कि वर्ष 2006-07 की तुलना में 2007-08 में उत्पादन में 2.45% की वृद्धि हुई है । तथापि वर्ष 2007-08 की तुलना में 2008-09 में कुल उत्पादन में 54015 मी. टन (11.48%) की गिरावट आई । वर्ष 2007-08 की तुलना में 2008-09⁷ में कुल निर्यातों में 31452 मी. टन की गिरावट आई । इसका तात्पर्य यह है कि निर्यातों में गिरावट के कारण उत्पादन में 31452 मी. टन की गिरावट आई । निर्यात में कमी के कारण उत्पादन में गिरावट भारत में उत्पादन में कुल गिरावट की 58.23% रही है । इस प्रकार निर्यातों में गिरावट उत्पादन में कमी का एक प्रमुख कारण है ।

66. घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि उसकी इकाइयों में से एक इकाई हैली टावर को बदलने के लिए एक माह तक बंद रखी गयी थी जो दैनिक रखरखाव का कार्य नहीं था । इस बंदी से लगभग 5000 मी. टन की उत्पादन क्षमता उपलब्ध नहीं रही । अतः इकाई को बंद किया जाना उन कारकों में से एक कारक भी है जिनकी वजह से उत्पादन में गिरावट आई है ।

67. **क्षमता उपयोग :** निम्नलिखित तालिका में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग से संबंधित संगत आंकड़े दिए गए हैं :

⁷ संदर्भ तालिका 14, पृष्ठ 76

तालिका 8

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
“ घरेलू उद्योग ” की स्थापित क्षमता (मी. टन)	328500	328500	377338	377338
आईओसी सहित समस्त भारतीय उत्पादकों की स्थापित क्षमता (मी. टन)	448500	448500	497338	497338

तालिका 9

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
“ घरेलू उद्योग ” का क्षमता उपयोग (मी. टन)	108.54	102.83	89.58	75.94
आईओसी सहित समस्त भारतीय उत्पादकों का क्षमता उपयोग (मी. टन)	104.34	102.36	94.57	83.71

68. “ घरेलू उद्योग ” के क्षमता उपयोग में वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक लगातार गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है । यह देखा गया है कि वर्ष 2006-07 की तुलना में 2007-08 की अवधि में उत्पादन में सुधार होने की बावजूद इस दौरान क्षमता उपयोग में गिरावट आई है । वर्ष 2007-08 में 48838 मी. टन तक घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता में वृद्धि होने की मुख्य वजह से क्षमता उपयोग में गिरावट आई है । वर्ष 2007-08 की तुलना में 2008-09 में क्षमता उपयोग में गिरावट मुख्यतः उत्पादन में गिरावट के कारण आई जिसकी वजह से निर्यातों में कमी आई ।

69. इसी प्रकार, समस्त घरेलू उत्पादकों (आईओसी सहित) के क्षमता उपयोग के विश्लेषण से भी यह पता चलता है कि वर्ष 2006-07 की तुलना में 2007-08 में क्षमता उपयोग में गिरावट स्थापित क्षमता में वृद्धि के कारण आई । वर्ष 2008-09 में क्षमता उपयोग में गिरावट घटते हुए निर्यातों की मुख्य वजह से आई है ।

70. लाभ एवं हानि : निम्नलिखित तालिका में एलएबी व्यापार से संबंधित घरेलू उद्योग के लाभ एवं हानि से संबंधित संगत आंकड़े दिए गए हैं :

तालिका 10

वर्ष	लाभ/मी. टन	लाभ (पीबीटी)
(इकाई)	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध
2005-06	100	100

2006-07	- 25.05	- 24.5
2007-08	- 40.73	- 39.71
2008-09	+ 0.47	+0.42

71. वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान घरेलू उद्योगों को घाटा हुआ है। वर्ष 2006-07 में यह घाटा 100% से अधिक क्षमता उपयोग के बावजूद हुआ था। अतः संवर्धित आयात घाटे का कारण नहीं था। वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान आयातों में वृद्धि हुई जबकि अधिकतम आयात 2008-09 में हुए। तथापि, वर्ष 2008-09 में लाभप्रदता में 41.20 प्वाइंट का सुधार हुआ जो काफी अधिक है।

72. लाभप्रदता की प्रवृत्ति आयातों में प्रवृत्ति के सामयिक नहीं रही है। इसका तात्पर्य यह है कि संवर्धित आयातों से भिन्न कारकों की वजह से उद्योग की लाभप्रदता प्रभावित हुई है।

73. रोजगार

आवेदकों ने अनुरोध किया है कि ये कंपनियाँ बहु-उत्पाद कंपनियाँ हैं और उद्योग के पूंजी गहन स्वरूप को देखते हुए रोजगार से गंभीर क्षति की वास्तविक मात्रा और गंभीर क्षति के खतरे का पता नहीं चल सकता है। कर्मचारियों की संख्या भी स्थिर रही है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है।

तालिका 11

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
“घरेलू उद्योग” में कर्मचारियों की संख्या (सं.)	1007	1007	1010	955

74. उत्पादकता : कर्मचारियों की संख्या के संबंध में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उत्पादन के समान प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है क्योंकि यह मुख्यतः उत्पादन पर निर्भर होती है।

तालिका 12

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
उत्पादकता/ कर्मचारी “घरेलू उद्योग” (मी. टन/कर्मचारी)	354	335	335	300

अन्य कारक

75. कीमत विश्लेषण : निम्नलिखित तालिका में एलएबी की घरेलू कीमतें दी गयी हैं । घरेलू कीमत में वर्ष 2005-06 से लगातार सुधार हुआ है । वर्ष 2007-08 की तुलना में 2008-09 में एलएबी की कीमत में 35% की वृद्धि हुई जबकि 2006-07 की तुलना में 2007-08 में एलएबी की कीमत में 2% की वृद्धि हुई थी ।

तालिका 13

वर्ष	वास्तविक बिक्री कीमत/ मी. टन
(इकाई)	रूपए
2005-06	62059
2006-07	63418
2007-08	64767
2008-09	87552

76. निर्यात : निम्नलिखित तालिका में समस्त भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यातों से संबंधित सूचना दी गई है :

तालिका 14

निर्यात के आंकड़ों का विश्लेषण

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
“ घरेलू उद्योग ” द्वारा निर्यात (मी. टन)	101852.32	107064.12	96855.47	82614.46
आईओसी सहित समस्त भारतीय उत्पादकों द्वारा निर्यात (मी. टन)	122313.32	138368.12	135473.47	104021.46

तालिका 15

निर्यात बनाम आयात

वर्ष	समस्त भारतीय उत्पादकों (आईओसी सहित) द्वारा निर्यातों की कुल मात्रा	भारत द्वारा आयात	भारत द्वारा निवल निर्यात
(इकाई)	(मी. टन)	(मी. टन)	(मी. टन)
2005-06	122313.3	4871	117442.3
2006-07	138368.1	21470	116898.1
2007-08	135473.5	45505	89968.47

2008-09	104021.5	73630	30391.46
---------	----------	-------	----------

77. भारत हमेशा ही एलएबी का जरूरत के अनुसार निर्यातक रहा है। तथापि भारत से होने वाले निर्यातों में वर्ष 2006-07 से गिरावट आई है। पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में भारत से हुए निर्यात में 2008-09 में 23.22% और 2007-08 में 2% की गिरावट आई। इसकी वजह से उत्पादन⁸ कम हुआ और क्षमता उपयोग कम रहा।

78. भारत के उत्पादकों के बीच अंतर-इकाई गतिशीलता : निम्नलिखित तालिका में भारत के अलग-अलग एलएबी उत्पादकों का प्रतिशत हिस्सा दिया गया है।

तालिका 16

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
कम्पनी	हिस्सा	हिस्सा	हिस्सा	हिस्सा
इंडियन ऑयल	11%	24%	26%	28%
निरमा	26%	21%	19%	19%
रिलायंस	41%	38%	36%	36%
टीपीएल	22%	17%	19%	17%
कुल	100%	100%	100%	100%

79. आईओसी के पास भारत की उत्पादन क्षमता की मात्र 11% थी परंतु वर्ष 2005-06 से उत्पादन के हिस्से में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2007-08 और 2008-09 में कुल घरेलू उत्पादन में आईओसी का हिस्सा बढ़कर क्रमशः 28% और 31% हो गया। यह वृद्धि एलएबी के अन्य उत्पादकों, जो “घरेलू उद्योग” हैं, की लागत पर हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि “घरेलू उद्योग” का हिस्सा आईओसी ने ले लिया है।

घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति

80. भारत एलएबी का जरूरत के अनुसार निर्यातक रहा है और उसने वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 में अपने उत्पादन का क्रमशः 26%, 30%, 29% और 25% का निर्यात किया। इससे यह पता चलता है कि एलएबी का निर्यात एलएबी के भारतीय उद्योगों का एक प्रमुख कारोबार है। वर्ष 2007-08 में स्थापित क्षमता में 48,838 मी. टन की वृद्धि की गयी थी परंतु उत्पादन में केवल 11,249 मी.

⁸ वर्ष 2007-08 की तुलना में 2008-09 में कुल निर्यातों में 31,452 मी. टन की गिरावट आई। निर्यात में गिरावट के कारण उत्पादन में गिरावट भारत में उत्पादन में आई कुल गिरावट की 58.23% थी।

टन की वृद्धि हो सकी जिसकी वजह से क्षमता उपयोग घटकर 100% से कम (94.57%) हो गया ।

81. वर्ष 2008-09 में निर्यातों में 31,452 मी. टन की गिरावट आई जिसकी वजह से घरेलू उद्योग के लिए बेशी क्षमता उपलब्ध हो गयी । चूँकि वर्ष 2007-08 तक बढ़ती हुई घरेलू माँग को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक थे । अतः घरेलू माँग को पूरा करने के लिए आयातों की प्रवृत्ति जारी रही जिसमें 20,843 मी. टन की वृद्धि हुई । भारतीय उद्योग घरेलू बाजार में शीघ्र पुनः स्थापित होने में समर्थ नहीं थे जिसे आयातों के लिए छोड़ा गया था क्योंकि क्रय पद्धति में परिवर्तन सामान्यतः धीरे-धीरे होते हैं । यह तथ्य ग्राफ 1⁹ से स्पष्ट हो जाता है जिसमें यह दर्शाया गया है कि आयातों में वृद्धि रैखिक रूप से हुई है और वर्ष 2005-06 के बाद आयातों में कोई तीव्र या अचानक वृद्धि नहीं हुई है । वस्तुतः आयातों की वृद्धि दर अचानक कोई वृद्धि नहीं हुई है । वास्तव में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में आयातों की वृद्धि दर वर्ष 2007-08 (111.95%) तथा 2006-07 (340.77%) की तुलना में 08-09 में कम (61.80%) रही है ।

82. भारतीय उद्योगों द्वारा निर्यात बाजार में उठाई गई हानि की भरपाई घरेलू बाजार में उतनी ही प्राप्ति द्वारा नहीं की जा सकी । यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि समस्त घरेलू उत्पादकों की कुल घरेलू बिक्री समान स्तर पर बनी रही । यह भी देखा गया है कि वर्ष 2007-08 में निर्यात में 2895 मी. टन की गिरावट आई और घरेलू बिक्री में 5687 मी. टन की वृद्धि हुई यद्यपि स्थापित क्षमता में 48838 मी. टन का विस्तार किया गया । वर्ष 2008-09 में निर्यातों में 2007-08 की तुलना में पुनः 31,452 मी. टन की गिरावट आई और इसी अवधि में घरेलू बिक्री में तदनुरूपी बढ़ोत्तरी नहीं हुई ।

83. सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख में भारत में किसी वस्तु का आयात इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी स्थितियों में होने पर रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का प्रावधान है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो । दूसरे शब्दों में रक्षोपाय शुल्क संवर्धित आयातों द्वारा गंभीर क्षति का पर्याप्त कारण होने की स्थिति में लगाया जा सकता है । गंभीर क्षति का निर्धारण विभिन्न आर्थिक कारकों के मूल्यांकन पर आधारित होता है । किए गए विश्लेषण से यह देखा जाता है कि प्रत्येक अलग-अलग कारकों, जिनका विश्लेषण गंभीर क्षति की मौजूदगी के निर्धारण के लिए किया गया है, का पर्याप्त संबंध संवर्धित आयातों से इतर कारकों से है ।

84. आयात तथा अन्य आर्थिक कारकों की प्रवृत्ति के विश्लेषण से यह पता चलता है कि संवर्धित आयातों से भिन्न ऐसे अन्य कारक हैं जिनसे घरेलू उद्योग का निष्पादन अत्यधिक प्रभावित हुआ है । ये हैं :

क. एलएबी व्यापार में आईओसी का प्रवेश;

⁹ संदर्भ पैरा 49

ख. निर्यातों में गिरावट; और

ग. घरेलू उत्पादकों की निर्यातों में मुछी डिजाइन;

85. जैसा कि ऊपर विभिन्न आर्थिक कारकों के विश्लेषण में विचार-विमर्श किया गया है घरेलू बाजार को प्रभावित करने में इन कारकों का योगदान संवर्धित आयातों की तुलना में काफी अधिक है। अतः कानून में की गई अपेक्षा के अनुसार कारणात्मक संबंध का अभाव है। इसके अलावा, समग्र मूल्यांकन से गंभीर क्षति का पता नहीं चलता है।

निष्कर्ष एवं सिफारिश

86. उपर्युक्त के आधार पर एलएबी के आयातों पर किसी रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती है।

[फा. सं. डी-22011/23/08]

प्रवीण महाजन, महानिदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF SAFEGUARDS, CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2009

FINAL FINDINGS

Sub. : Safeguard investigation concerning imports of Linear Alkyl Benzene into India

G.S.R. 832(E).—Having regard to the Custom Tariff Act, 1975 and the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 thereof.

A. PROCEDURE

1. An application was filed under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 [hereinafter referred to as "Safeguard Rules"] by (i) M/s. Reliance Industries Ltd., Mumbai, (ii) M/s. Tamilnadu Petroproducts Ltd., Chennai, (iii) M/s. Nirma Ltd., Ahmedabad (iv) M/s. Indian Oil Corporation Ltd., New Delhi (Supporter) seeking imposition of Safeguard Duty on imports of Linear Alkyl Benzene into India alleging that increased imports of Linear Alkyl Benzene is causing and/or threatening to cause serious injury to the domestic producers of Linear Alkyl Benzene in India. Having satisfied that the requirements of Rule 5 were met with, safeguard investigation against imports of Linear Alkyl Benzene was initiated vide notice of initiation dated 19th December 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary on the same day.
2. A copy of the notice was sent to the governments of major exporting countries through their embassies in New Delhi. A copy of initiation notice was also sent to all known interested parties listed below:

Domestic Producers

- (i) M/s. Reliance Industries Ltd., Mumbai.
- (ii) M/s. Tamilnadu Petroproducts Ltd., Chennai.

- (iii) M/s Nirma Ltd., Ahmedabad
- (iv) M/s Indian Oil Corporation Ltd., New Delhi (Supporter)

Importers

- (i) Fena Pvt Ltd, A-67&68 Mettupalayam, PIPDIC Industrial Area, Pondicherry, 605009
- (ii) Skill Dyechem, Village Panchpara, PO Radhadasi- 711309, Howrah, West Bengal
- (iii) Sai Sulphonates P Ltd, 21, Princep Street, Kolkata 700072, West Bengal
- (iv) Rohit Surfactants Pvt Ltd. (GHARI), KDC- Chaubepur unit, 117/H-2/202, Pandu Nagar, Kanpur- 200095, Uttar Pradesh

Exporters

- (i) Iran Chemicals Industries Investment Companies, No.91 Saidi St Africa Ave Teheran (19679) Iran .
- (ii) Gulf Farabi Petrochemical Co. Al-Jubail Industrial City 31961, P.O. Box 11763, Kingdom Of Saudi Arabia
- (iii) Seef Limited, Qatar, Seef Limited, Post Box: 50077, Mesaieed, State Of Qatar
- (iv) Kolmar Group Ag, Laubehof, Metallstrasse 9, 6300 Zug, Switzerland

- 3. Questionnaires were also sent, on the same day, to all known domestic producers and importers and exporters and they were asked to submit their response within 30 days.
- 4. Request to consider them as an interested parties were received from the following parties and all the requests were accepted:

- 1. M/s Fashion Suiting (P) Ltd.
3, Chhabra Mansion,
Puri Road
Bhilwara-311001
- 2. M/s Shree Unicon Organics Pvt. Ltd.
BS, Apjee,
130 Mumbai Samachar Marg
Mumbai-400023
- 3. A.R Salphonates Pvt. Ltd.
Plot No. N41
Additional Ambarnath,
MIDC Anand Nagar,
Dist.Thane -421501
Maharashtra

4. Tamil Nadu Small Scale Soap & Detergents
Chateau 'D Ampa, IV Floor ,
No37, Old No. 110
Nelson Manickam Road,
Chennai-600029
5. Shanati Nath Detergents (P) Limited
P-15, Kalakar Street,
Kolkata-700007
6. Rajaram Group of Industries
14, Azeez Nagar IIInd Street
Kodambakkam
Chennai.600024
7. Kishors Sons Detergents Pvt. Ltd.
15-9-469, Mahanoongunj
Hydrerabad – 500012. (A..P.)
India
8. Advance Surfactants India Limited
511/2/1. Rajokri,
New Delhi-110038
9. A.R. Stanchem Pvt. Ltd.
Exporters & Manufacturers
Old Court House Street
2nd Floor, Coke & Kalvay Building
Kolkata 700001
10. New India Detergents Limited
A-2/25 Model Town -I
Delhi-110009
11. M/s Small Scale Detergents
43 European Asyum Lane ,
Kolkata -700016
12. Standards Surfactants Ltd
8/5 Arya Nagar,

Kanpur-208002

13. Gora Mal Hari Ram Ltd.
39, Najafgarh Road, Indl. Area
New Delhi -15
14. Detergents Manufacturers Associations
148 New Okhla, Industrial Complex-I
New Delhi-110020
15. Barkur Surfactants Pvt. Ltd.
Unitop House , East West Estate
Safed Pool, Andheri Kurla Road
Mumbai-400072
16. ISRO Product

Unitop House , East West Estate
Safed Pool, Andhari Kurla Road
Mumbai-400072
17. S. Kumars Detergents Pvt. Ltd
4-D, Local Shopping Centre ,
A Block , Ring Road,
Naraina , New Delhi-110028
18. Saci- Chem
59 & 60 DSIDC, Industrial Complex
Okhla , Phase-I, New Delhi-110020
19. Hipolin Limited ,
Madhuban , 4th Floor , Ellis bridge,
Ahmedabad -380006
20. All India Federation of Detergents Manufacturers,
511/2/1, Rajokari,
New Delhi -38
21. Maharashtra Small Scale Soap Detergents Manufacturers Association,
Shree Veerabai Maa Niwas,

Shastri Nagar Square, Nagpur-8,

Maharashtra

22. Gujrat Small Scale Detergents Manufacturing Association,
C/o Kishore Soap Industries,
Maheshwari Mill Road,
Tavdipura, Shahibaug,
Ahmedabad – 380004
23. Power Soaps Ltd
62-B, North Boag Road, T. Nagar,
Chennai-600017
24. M/s Bhaskar Venkatesh Products Pvt. Ltd.,
Bhawani Complex,
35, Hanumanganj,
Near Jumerati Corner,
Bhopal – 462001 (M.P.)
25. M/s Abdos Consumer Care Limited,
Jalan Compound,
Bombay Highway, NH No. 6,
Biparannapara, Howrah – 711411
26. M/s Prabu Soap Works,
P.Box No. 5115, 3/A1,
Thayir Itteri Road,
Kannappan Nagar,
Rathinapuri (P.O.) Coimbatore – 641 027..
27. M/s Shriram Bharat Chemicals & Detergents (P) Ltd.,
1/56, Sanjay Gandhi Nagar,
Nochipalayam Road,
46, Pundhur Village, Erode – 638002
28. M/s Bharathi Soap Works,
1st Line,
Nallacheruvu,
Guntur – 522 003 (A.P.)

- 29 M/s Sabari Detergents,
191, Valparai Road,
Avalchinnampalayam.
Zamin Kottampatti.
Pollachi – 642 123
30. M/s S.S. Enterprises,
No. 43, SIDCO Industrial Estate,
Dindigul – 624 003.
31. M/s Man Chemicals,
20/1, Sivakami illam,
Lakshmi Sundaram Colony.
Behind M.S.P. School Ground,
Dindigul – 624 005
32. M/s Sakthi Traders,
No. 5/810, Malligai Road,
Kootturavu Nagar,
Dindigul – 624 005
33. M/s Shiva Soap Works,
Nanthavana Patti,
Dindigul - 624005
- 34 M/s National Soaps Company,
138/1 Semmam Palayam Pirivu,
Nasiyanur Road,
Villarasampatti Nall Road,
Nasiyanur (P.O.)
Erode - 638107, T.N.
- 35 M/s Sree Manakula Vinayaga Chemicals,
R.S. No. 89/1-F & D, Pannithittu Road,
Kirumampakkam,

Puducherry – 607 402

36. M/s Silver Chemicals,
1/255, Main Road,
Valayankulam,
Madurai – 625 022,
Tamil Nadu
37. M/s Raja Chemical Works,
137, Sami Iyer New Street,
Coimbatore – 641 001.
38. M/s Sree Pushpam Indutries,
R.S. No. 121/1 & 63/7,
Madagadipet & Tirubuvani Village,
Tirubuvanai Post,
Pondicherry – 605107.
39. M/s Lingam Chemical Industries,
8/55, Ambai Road,
Alangulam – 627851,
Tirunelveli, Tamilnadu
40. M/s Anand Chemicals,
13/4 Kamarajar Nagar,
Avaniyapuram (P.O.)
Ayanpappakudi
Madurai – 625012 (T.N.)
41. M/s Hi-Tech India,
No. 1, Vengur Road,
Thiruverumbur,
Trichy – 620 013.
42. M/s Flora Chemicals,
2/226, Ammatchi Amman Koil Street,
Uthangudi,
Madurai – 625 107.
Tamilnadu
43. M/s Devi Cropscience Pvt. Ltd.

P.B. No. 274, 29-A,
Workshop Road,
Madurai – 625 001,
Tamilnadu

44. M/s Shunmuga Industries,
139-ABC, Sundakkamuthur Road,
Selvapuram,
Coimbatore – 26.
45. M/s Cymose Products,
4/139. Ayyanarpuram Main Road,
Panaiyur (P.O.),
Madurai – 625009
46. M/s Raceme Products,
2/221., Ayyanar Kovil Street,
Uthangudi,
Madurai – 625 017.
47. M/s Orchid Chemicals,
183, Nedungulam Road,
Pottapalayam,
Sivagana Dt. 630611
Tamilnadu
48. M/s Muthukani Industries,
2/104 (1)- New Colony,
Andipatti P.O.
Alangulam – 627 851
49. M/s Vardaan Detergent Private Limited,
Plot No. 131, Sector – 24,
Faridabad – 121005
50. M/s Reino Industrial Organics Pvt. Ltd.,
B-93, Mayapuri Phase – I,
New Delhi – 64.

5. Requests for an extension of time to submit their replies were made by some of the interested parties. After taking into account the time limits for completing the investigation within the prescribed period, requests for extension of time were allowed and the parties concerned were accordingly informed. Besides these various representations were received without any specific request to become interested parties. Many issues raised by them are similar to the submissions raised by other interested parties. These have accordingly been considered.
6. After expeditious conduct of investigation preliminary findings were issued on 30th January 2009. However, no provisional safeguard duty has been levied.
7. A public hearing was held on 23rd July, notice for which was sent to all interested parties besides posting the notice on the Website. All interested parties who participated in the public hearing were requested to file a written submission of the views presented orally in terms of sub rule (6) of rule 6 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997. Copy of written submission filed by one interested party was made available to all the other interested parties. Interested parties were also given an opportunity to file the rejoinder, if any, to the written submissions of other interested parties. All the views expressed by the interested parties either in the written submissions or in the rejoinders were examined and have been taken into account in making appropriate determination.
8. The information presented by domestic producers with regard to their production, sales, and other injury parameters were verified by on-site visits to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. Further, the cost data has been also verified and certified by independent cost accountant. The non confidential version of verification report is kept in the public file.
9. In pursuance of sub-rule (1) of rule 11 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, the Central Government extended the period of investigation upto and inclusive of 18th day of November, 2009 for submission of final findings on safeguard investigation concerning imports of Linear Alkyl Benzene into India vide Notification No.123 / 2009-Customs (N.T.) dated 18th August, 2009.
10. As there are large numbers of interested parties, individual submissions by these interested parties are being recorded in a consolidated manner. However, submissions made by those who attended the Public Hearing are being recorded in the Final Findings, individually, in brief.

VIEWS OF DOMESTIC PRODUCERS OF INDIA:

11. The views of the Applicants in brief are as follows:
- a. The product is defined as “All Linear Alkyl Benzene, Mixed Alkyl Benzene falling under the tariff description of Customs Heading 3817 00 11. The above product is generally known as ‘Linear Alkyl Benzene’ (for short “LAB”) in commercial market parlance. The subject goods are used for manufacture of Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid or the Sodium Salt of Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid. All Linear Alkyl Benzene and the subject goods have been classified under chapter heading 38.17 of the Customs Tariff Act, 1975.
 - b. Rule 2(c) elaborates the concept of “increased quantity” so as to mean increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production. The imports have increased not only in absolute terms but also in relation to the production and demand. Imports which were a meagre 9854MT in the year 2004-05 rose four and a half times in the year 2007-08. Further, the quantities increased by 62% in the latest period of April 2008 – March 2009 increasing the problems of the Domestic Industry. An examination of the trend of imports would clearly indicate that the imports have shown an exponential increase with the quantities doubling every year with the exception of 2005-06. Imports have further gone up in the first quarter of 2009-2010 (April-June) to 17783MT from 11545MT during the corresponding period of the previous financial year i.e., an increase of a whopping 54%. A comparison of the imports between the first half of 2008-09 (25001MT) and the second half (48629MT) also clearly establishes that the situation with regard to imports has worsened in the latter half of the year inasmuch as the increase is 94%.
 - c. As regards the quantum of imports in relation to production, the imports which were a meagre 2.66% of the total production by the Domestic Industry increased to 6.36% in 2006-07, then to 13.46% in 2007-08 and subsequently to 25.70% in the year 2008-09.
 - d. Thus, the data establishes beyond any doubt that there is a tremendous surge in imports of the subject goods in absolute terms, rate of increase as well as in relation to the total production of the Domestic Industry. It is pertinent to note that the phenomenal increase in the year 2008-09 has taken place despite the fact that there was global slowdown in the second half of the last financial year.
 - e. With regard to the issue of “serious injury”, the Domestic Industry drew the attention of the DG to paragraph 8 of the Annexure to the Safeguard Rules, which make it obligatory for the DG to evaluate all relevant factors “of an objective and quantifiable nature” only. The Domestic Industry submitted that they have suffered serious injury on account of the sudden and huge increase in imports. The total sales of the Domestic Industry was to the tune of 211155MT in the year

2004-05 which has been consistently falling despite an increase in total demand. The most significant fall has been witnessed in the year 2008-09 to 168744MT from a level of 184212MT in the preceding year. The applicant Domestic Industry constitutes about 72% of the total domestic production and is the "Domestic Industry" in terms of Section 8B sub-section 6(b)(ii) of the Customs Tariff Act.

- f. Imports have increased from 3.82% in 2004-05 to 21.18% in 2008-09 thus, taking away as much as 17.36% of the Domestic Industry's market. The percentage of share taken away by imports will still be higher if the sales of only the applicant Domestic Industry are taken into account. A great majority of LAB imports coming to India are from Qatar, Iran and Saudi Arabia. Roughly 70% of the combined capacities of LAB in these countries and other Middle East countries are earmarked for exports. The geographical proximity of these countries combined with the strong LAB downstream sector in India, provides a huge attraction for these countries to direct their exports to India. The capacity is likely to go up further with another plant in Egypt.
- g. The production of the Domestic Industry has also come down drastically from a level of 338010 MT in the year 2007-08 to 286549 MT in 2008-09, clearly indicating that the Domestic Industry has suffered on account of fall in production. The capacity utilization of the Domestic Industry has suffered significantly during the year 2008-09. The Domestic Industry had a very healthy capacity utilization of 113% and 109% in the years 2004-05 and 2005-06 which has fallen to a meagre 76% in 2008-09.
- h. It is important to note that in the LAB industry, it is critical for the plants to operate at high levels of capacity utilization in order to reduce its average fixed cost per unit. Any fall in capacity utilization directly affects their profitability and the long-term viability. In the facts of the instant case also, it is clear that the Domestic Industry has suffered on account of the surge in imports which has led to lower levels of capacity utilization and the resultant fall in profitability of the Domestic Industry.
- i. Due to the increased imports and consequent lower levels of capacity utilization, the Domestic Industry has suffered enormously on the profitability front. From a positive profit level of *** (indexed at 100), the Domestic Industry has now been reduced to a situation of losses in the year 2006-07 and 2007-08. The Domestic Industry has made a negligible profit in the year 2008-09, therefore, the indexed number shows as zero.
- j. The average net sales realization of the domestic industry has increased over the injury investigation period. However, this increase in the average net sales realization of the domestic industry can be attributed as the direct result of increase in the cost.

- k. As regards the interests of End-Users of LAB, it was submitted that the decision of the Hon'ble Delhi High Court is not applicable as it does not make it obligatory or empowers the DG to pass an order based on public interest issues. Without prejudice to the fact that the interested parties do not have a legal right to compel the DG to address public interest issues in its findings, it is submitted that the interested parties have not brought forth any evidence or even information to substantiate their case.
- l. None of the importers (except HUL) has bothered to respond to the specific information called for by the DG vide its letter dated 17.7.2009. Even HUL has apparently provided the information for selective brands only making it impossible for the DG to carry out any meaningful analysis. Further, there is no basis of making assertions like "20 crore households will be adversely affected if duties on LAB is imposed".
- m. The importers/end-users have not provided any information whatsoever as to how the employment situation in the detergent industry was impacted when the prices of LAB had gone up due to the overall increase in the crude prices. It would be apparent that the importers are merely raising the bogey of employment and larger public interest to protect their profit margins at the cost of the beleaguered LAB industry. The fact is that imposition of safeguard duty will not only allow the domestic producers to face increased imports but will benefit the buyers of LAB as well as the final end users/consumers in the long run.
- n. Various plants of the domestic industry were shut down due to piling of inventories due to pressure from increased imports coupled with fall in profits and low return on capital employed. The details of closure have been submitted to the DG on a confidential basis. In any case, we submit that the fact, that the plants of the Domestic Industry have been closed for long periods on account of market conditions, has been verified by the DG (Safeguards) officials.
- o. It is submitted that the domestic industry has only requested for imposition of safeguard duty on imports of LAB in accordance with the law so as to enable them to adjust to the new situation of competition offered by the increased imports. The purpose of its imposition is to provide sufficient time to the domestic industry to make positive adjustments to meet the situation arising due to increased imports. If the Domestic Industry is permitted to increase its capacity utilization to the levels which it had comfortably achieved in the past, the financial situation of the Domestic Industry would considerably improve. As stated earlier, the high level of capacity utilization for the LAB industry is of critical importance for its long term commercial viability.
- p. Imposition of safeguard duties of at least 20% for a period of one year from the date of imposition followed by 15% in the second year and 10% in the third year has been requested. The levels of duties requested shall allow the domestic

industry to increase the production and capacity utilization. It will also reduce the cost along with several other measures proposed to be undertaken.

VIEWS OF EXPORTING COUNTRY GOVERNMENTS AND EXPORTERS

12. The Government of Saudi Arabia and Gulf Farabi Petrochemical Company Limited attended the Public Hearing through their representatives. The summary of their written submissions, submissions made during Public Hearings and rejoinder are as follows:
13. It is Gulf Farabi's view that, during this public hearing, ample evidence was given to the DGSG that there was no case in this particular instance for the imposition of safeguard measures, in particular in the light of extremely high standards laid out by Indian and WTO rules on safeguards.
14. A large proportion of LAB imported from Saudi Arabia is being imported under an Export Oriented Unit scheme
15. Petitioners have presented additional evidence concerning the evolution of imports, which cannot be relied upon
16. The evolution of imports during the period of investigation is a mechanical consequence of the export-driven strategy of the Indian producers
17. Imports of LAB are not coming at a low price
18. Petitioners have not suffered any serious injury as
 - a. level of production is stagnant
 - b. market share of petitioners is very high in the globalised world
 - c. capacity utilization is very high
 - d. Loss in profits, if at all present, is not attributable to increased import.
19. The injury, if any, is not on account of increased imports.
20. The entry of IOC into Indian LAB market has radically altered the market forces in that country.
21. There is no unforeseen development as flow of LAB to India from Middle East Region was foreseeable and predictable.
22. The export performance also resulted from a well thought-out strategy by the Indian producers to deliberately favour exports in the global market at the expense of the Indian market and to the detriment of the Indian users and consumers
23. There is no emergency situation.
24. Based on above there is no justification for imposition of safeguard duty.
25. In the present context, where the global crisis generates considerable protectionist pressures, it is particularly important that national authorities avoid measures which would not be fully justified under the WTO.
26. The Government of Qatar, SEEF Ltd, Mesaieed and others have made the following averments through their written submissions:

- a. LAB imports are coming in India at International prices like they come into any other country of the world.
 - b. Indian LAB producers are exporting about 30% of their production at about the same international price or at times even lower than the price at which LAB is imported into the country.
 - c. The customs duty of 7.5% is sufficient protection for the domestic industry.
 - d. The safeguard duty will make detergent industry globally uncompetitive.
 - e. SEEF Limited Qatar manufactures LAB using the more advanced Detal process of UOP and the product quality from our plant is preferred by detergent industry. In India only IOC and Nirma produces by this process.
 - f. The Middle East LAB suppliers are supporting the India Detergent Industry directly and indirectly by not only supplying LAB to them but also by supplying raw material for the Indian LAB manufacturers.
 - g. There has been regular supply of LAB from Middle East and thus there is no element of surprise.
 - h. There is no significant increased import causing serious injury.
 - i. There is no serious injury.
27. M/s Hindustan Unilever Ltd submitted the following points through their written averments and submissions during Public Hearing, rejoinders etc:
- a. The safeguard proceedings are extraordinary remedies and the standard of 'serious injury' is very high. Safeguard Measures should be resorted to only in emergent situations only.
 - b. The word recent implies some form of retrospective analysis. It does not mean analysis of the conditions immediately preceding the authority's decision. They referred to decision of WTO panel in US-Line Pipe safeguards. The increase in import is not sudden and significant. It is also not dramatic. The imports meant to manufacture final products destined for export should be excluded. If these imports are excluded the share of import in 2006-07 will become 2.98% and 7.05% in 2007-08.
 - c. There is no "significant overall impairment" in the position of the domestic industry. The companies seeking safeguard duty protection are financially strong and large conglomerates.
 - d. Domestic sales are being substituted by Exports, which are more than 40% of the Domestic sales. The claim of fall in market share is misleading as sales were increasing.
 - e. The Capacity utilisation is very high.
 - f. The safeguard Petitioners have not provided a non-confidential summary of the information claimed to be confidential. This seriously impairs the right of

- the interested parties to make meaningful submissions. The actual data of profit is not available with the interested parties.
- g. There is no causal link. Plant shut downs are not on account of exports. The injury is on account of high crude price. The injury is also on account of oversupply in the domestic market. The domestic industries have been flourishing. There is a lack of adequate summary of the restructuring plan and excess confidentiality.
- h. 'Public interest' considerations play an important role in the administration of trade remedial measures such as safeguard duties. They also quoted the case of United Phosphorous vs Director General safeguard, 2000 (118) ELT 326 (Del).
- i. There is one to one relationship between LAB and detergent price.

Summary of earlier submissions:

- j. The domestic industries are overcharging the users. LAB is an intermediary product and is an input in the manufacture of detergent bars and powder and constitutes around 50 to 60% percent of the final product cost. Any increase in the prices of the input (LAB) will most certainly increase the costs of final products.
- k. The price of LAB has increased and such increase in prices has resulted in a proportionate increase in the prices of detergents and has impacted nearly 20 crore Indian households since detergent powders and bars are consumed in every Indian house. Further, the detergent industry in India comprises of thousands of tiny units, small scale industries and a few medium and large scale manufacturers. The detergent industry is highly labour intensive as compared to the LAB industry. It employs over five lakh workers, which is significantly high as compared to the LAB industry which employs only around 500 workers. In the event that safeguard duties are levied on imports of LAB into India, it may adversely affect the viability of the downstream detergents industry and thereby affect the very livelihood of lakhs of workers employed in this industry.
- l. The total production of LAB by the domestic industry has increased. However, parallel to the decrease in the share of the domestic industry in total domestic consumption there has been a corresponding increase in domestic industry's export production. This implies that there has been a significant shift in the sales pattern of the domestic industry which is veering more towards exports. The share of exports in the total installed production capacity is significantly high, which goes on to show that LAB produced in India is increasingly being diverted to the export market. The loss in domestic market share by the domestic industry if any, is self inflicted and does not show any degree of injury to the domestic industry.

- m. Petitioners have been operating at significantly high level of capacity utilization.
 - n. It has been a consistent practice with the Hon'ble Designated Authority to determine the existence or threat of serious injury to the domestic industry on the basis of the most recent data on imports.
 - o. The Petitioners have failed to establish the existence of a causal link between increased imports of LAB and the alleged serious injury being suffered by them.
 - p. The claims by the Petitioners on their plants being shut down are misleading. Both Tamilnadu Petroproducts Ltd. as well as Reliance Industries Limited are large petro-chemical manufacturers and the information on plant shut downs relates to temporary shut downs possibly for general maintenance and up-gradation purposes or unavailability of feedstock. Contrary to the claims made by the Petitioners, their plants were shut not because of the increase in imports of LAB into India and their inability to sell LAB, but for temporary reasons such as maintenance for general wear and tear. Instead the Petitioners continue to produce and sell LAB both in the domestic market and the export market.
 - q. The consumers of LAB have been facing several constraints in procuring LAB from domestic sources. This forced the users of LAB to make alternate arrangements and explore the option of meeting their demand through imports. The difficulty in procuring LAB domestically has been further aggravated by the increasing trend amongst the domestic producers to substitute domestic sales by exports.
 - r. A review of the details provided by the domestic industry in its petition shows that their efforts to adjust to the increased imports are grossly inadequate and further highlights the incongruity of their claims that they are suffering injury due to increased imports.
 - s. In light of the above, there exists no serious injury or threat of serious injury to the domestic industry for LAB due to increased imports of LAB into India.
28. Advance Home and Personal Care Ltd., New Delhi, Advance Surfactants India Ltd, New Delhi, A.R.Stanchem Pvt.Ltd, Kolkata, New India Detergents Ltd, New Delhi, M/s Fena (P) Ltd, New Delhi, Rohit Surfactants (P) Ltd, Kanpur, Sai Sulphonates Pvt Ltd, Kolkata, Shantinath Detergents (P) Ltd, Kolkata, Small Scale Detergents & Soap manufacturers Association, Kolkata and Standard Surfactants Ltd, Kanpur filed written submissions and attended Public Hearing as well as submitted rejoinders. The summary of their arguments put forth are:
- a. Initiation is in violation of Article XIX of GATT 1994 as no unforeseen developments appear to have occurred.
 - b. This increase cannot be treated 'significant enough, sharp enough and sudden enough'. Though imports increased in 2007-08 over 2006-07, such increase cannot be treated as 'recent enough' especially when the investigation was initiated in December 2008.

- c. The data presented by domestic producers during the public hearing is totally different from what has been recorded in the Preliminary Findings by the Director General
- d. Even the basic data relating to the case has not been provided. Such data shall never be accepted by DG Safeguards as it would amount to a violation of the principles of natural justice
- e. It may be seen that with the entry of IOCL into the industry, other domestic producers are facing a lot of pressure. The shares of other three producers have come down and the share of IOCL has increased.
- f. There is no 'serious injury' caused to the domestic producers.
- g. The prices of LAB fixed by domestic producers have always been same. Even the price revisions are in tandem. Further the domestic producers have been charging exorbitantly higher prices even when the crude prices have fallen.
- h. The Public Interest has not been considered especially when Applicants are mega corporations whose turnover individually is far higher than the collective turnover of all the members of the Detergent Manufacturers Association taken together.
- i. The import data if taken from INFODRIVE is different from the IBIS and DGCIS figures. If INFODRIVE figures are taken the increase in import is small.
- j. If IOC is also considered part of Domestic industry, then total sales would be 307503 MT in 2006-07, 320212 MT in 2007-08 and 290014 MT in 2008-09. Similarly total production including that of IOC would be 459808 MT, 471010 MT and 412549 MT in 2006-07, 2007-08 and 2008-09 respectively. If INFODRIVE figures of import are taken and IOC figures are added in economic parameters, the share of import is 7%, 12% and 14% in 2006-07, 2007-08 and 2008-09 respectively.
- k. The profitability has improved in 2008-09 even when imports increased.
- l. The onus to prove public interest lies with the domestic industry.
- m. The restructuring plan is not elaborate and viable.

The earlier submissions:

- n. Import statistics is outdated and may not represent the current state of affairs. The investigation was initiated in December 2008. However, the petition presents import statistics only up to Financial Year 2007-08.
- o. The plants of domestic producers are running and hence the claim of closure of plants is false.
- p. There is no fall in production.
- q. The end-users of LAB are medium and small sized enterprises as compared to the large industrial groups who manufacture LAB. The LAB producers have

been acting as a cartel and are maintaining their domestic prices at artificially higher levels. Domestic selling prices charged by all the four domestic producers have always been in tandem. Domestic selling prices have been significantly higher than the prices at which they export to other countries; Import prices are somewhere in between their domestic prices and export prices.

- r. Indian end users of LAB have been paying very high prices charged by the domestic producers of LAB and the present petition seeking imposition of safeguards duty is only to preserve superlative profits.
- s. LAB is already subject to basic customs duty at the rate of 7.5%. On the finished consumer detergent products, there is a peak import duty of 10%. Therefore, imposition of safeguards duty on LAB will lead to an inverse duty structure where the custom duty on a basic raw material will be higher than the duty applicable on the finished products.
- t. Any increase in the cost of LAB will directly affect the prices of detergents and will eventually lead to lower production and sale of detergents. As against 4 manufacturers of LAB, there are over 4000 manufacturers of detergents in India. They employ over 500,000 persons as against 500 persons employed by LAB producers. Thus, levy of safeguard duty will jeopardize the employment opportunities of a large number of employees than non-levy of safeguard duty.
- u. 'Critical Circumstances' do not exist in the present case warranting imposition of provisional safeguard measures.
- v. It has further been contended that it is important and mandatory to consider 'all relevant factors' under Art. 4.2(a) to arrive at Serious Injury.
- w. Further import prices of LAB are mostly higher than export price of Indian LAB manufacturers. It may be observed that at least 30% of the total domestic production is being exported by the domestic industry. It is unrealistic to assume that if the domestic industry is suffering a loss in domestic market, they will export such high quantities at lower prices.
- x. As per the market intelligence available with the importers, the average net sales realization and margin of domestic industry range between -5% to 23%.
- y. No case of critical circumstances has been made out.
- z. They have also contended that the imposition of provisional or final measures would be against 'public Interest' and Article 3.1 of the AoS obligates the investigating authorities to hold public hearings or provide other appropriate means for interested parties (importer, exporters, producers, etc.) to present their views.

- aa. Further, the Initiation Notice dated 19th December 2008 does not contain any reference to unforeseen developments, which occurred as a result of obligations undertaken by India before WTO.
- bb. Capacity addition in the four exporting countries from Middle East is just 15,000 Tons or a meager 4.6% and therefore, does not present a threat of material injury to domestic industry in the absence of which preliminary safeguards duty should not be levied. Such insignificant capacity additions are common in business and at best, the above changes can be termed as "developments" but can never be termed as "unforeseen developments as a result of obligations undertaken by India".
- cc. The comparative advantage in raw material is reflected in the prices and volumes for which no safeguard duty can be imposed. The oil production in Middle East is a widely known factor since several decades. The objective of trade remedy measures including safeguards is not to allow companies to earn 'super normal profits' by seeking protection from their national governments.
- dd. There is no credible restructuring plan that has been presented by the domestic Industry.
- ee. It is undisputed that cost of production of LAB is completely based on crude prices, but the domestic prices do not reflect the falling crude prices.
- ff. The Initiation is in violation of Article XIX of GATT 1994 as no unforeseen developments appear to have occurred Further, in terms Article XIX of GATT 1994, a safeguard measure can only be imposed when there is a sudden surge in imports as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under GATT, which causes or threatens to cause serious injury to domestic producers of like or directly competitive products in the territory of that contracting party..
- gg. The capacity addition in the four exporting countries from Middle East i.e Iran, Qatar, Saudi Arabia & UAE is just 15,000 Tons or 4.6%.
- hh. The Parameters mentioned in the petition do not support 'serious injury' or 'threat of serious injury'.
- ii. Further there appears to be no co-relation between the proposed reduction in cost and the level of duties in force or the level of duties sought by them.

Other Submissions:

29. The summary of submissions made by those interested parties who have not attended Public Hearings are as follows:

- a. The price of LAB has increased and such increase in prices has resulted in a proportionate increase in the prices of detergents and has impacted nearly 20 crore Indian households since detergent powders and bars are

consumed in every Indian house. Further, the detergent industry in India comprises of thousands of tiny units, small scale industries and a few medium and large scale manufacturers. The detergent industry is highly labour intensive as compared to the LAB industry. It employs over five lakh workers, which is significantly high as compared to the LAB industry which employs only around 500 workers. In the event that safeguard duties are levied on imports of LAB into India, it may adversely affect the viability of the downstream detergent industry and thereby affect the very livelihood of lakhs of workers employed in this industry.

- b. The four constituents of the domestic industry are multi-product, large manufacturing companies. Manufacture and production of LAB constitutes only a small percentage of the overall business of these companies. Given the large size of the Petitioners and the relatively small presence of LAB in their product portfolio, it is unlikely that they may suffer 'significant overall impairment' due to increase in imports of LAB alone.
- c. There is no serious injury as Domestic Sales are being substituted by exports and India is net exporter of LAB.
- d. Indian Industries are adopting export oriented approach.
- e. The petitioners are operating at very high capacity utilization.
- f. Plant shut downs are on account of routine maintenance and business decision and not on account of import.
- g. Injury is on account of oversupply in the domestic market.
- h. Domestic industry has been flourishing as LAB is a very small proportion of their business.
- i. The restructuring plan is not sufficient.
- j. The public interest is in favour of non-imposition of Safeguard duty as there are large numbers of end users employing large number of people, who manufacture detergent.
- k. The Domestic Industry is unable to provide sufficient LAB to the end-user.
- l. There is no serious injury and thus no safeguard duty should be imposed.

EXAMINATION AND FINDINGS :

30. I have carefully gone through the case records and the replies filed by the domestic producers, users/importers, exporters and exporting government. Submissions made by the various parties and the issues arising therefrom are dealt with at appropriate places in the findings below.

Methodology and Source of Information:

31. For the purpose of import data reliance has been placed on DGCIS figures up to FY 2006-07 and IBIS for the subsequent period. The transaction wise details of the information have been kept in the public file. The other economic parameters relating to all manufacturers of India have been sourced from the applicants. If any other information is used the source is mentioned with the information.

Product under Investigation:

32. The product under investigation is "All Linear Alkyl Benzene, Mixed Alkyl Benzene. It falls under sub-heading No. 38170011 of Schedule I of the Customs Tariff Act 1975, sub-heading No. 38170011 of ITC and sub-heading No. 38170011 of HSN. The subject matter of investigation is only Mixed Alkyl Benzenes and Linear Alkyl Benzenes and not Mixed Alkyl Naphthalenes. The above product is generally known as 'Linear Alkyl Benzene' (for short "LAB") in commercial market parlance.
33. The domestic industries use Kerosene, (Extracted - C10-C13 Paraffins) and Benzene as raw materials for the production of Linear Alkyl Benzene. C10-C13 Paraffins are extracted from the Hydrobon Molex Process, from Feedstock Kerosene. These Paraffins are converted to their Olefins, by selective dehydrogenation, at high temperature. The C10-C13 Olefins are then alkylated to Benzene, to form Linear Alkyl Benzene. The linear alkylbenzenes produced from C10C13 linear olefins are useful detergent intermediates and can be readily sulfonated to yield linear alkylbenzene sulfonates. These compounds constitute the "active" ingredients of household detergents. They are surface active compounds (surfactants) which are combined with various builders (often inorganic salts) to make up a detergent. In short, LAB is used as an important input by the detergent industries.
34. Regarding product under investigation, M/s Gulf Farabi Petrochemical Co. Ltd. contended that the product supplied by them is different from the product sold domestically in India by the Domestic Industry. The Gulf Farabi LAB possesses a different carbon chain distribution pattern when compared to the domestic product and has lower molecular weight than the domestic manufactured product. The imported LAB from Gulf Farabi has better detergency performance. Therefore, these are not like or directly competitive products.

35. The issue has been examined. The production process of Linear Alkyl Benzene as well as design of the manufacturing plant may have slight bearing on the physical or chemical characteristic of the product. As per the information provided by M/s Gulf Farabi, the imported LAB as well as Domestic LAB has identical appearance (i.e clear colorless liquid), Bromine Index, Paraffin content, 2-Phenyl Alkanes, Normal LAB content and Moisture. However, the average molecular weight of Indian LAB varies between 235-239 and that of Gulf Farabi varies between 238-242. This contended difference in quality is too small to have any bearing on substitutability and their ability to be competitive. The interested parties themselves have contended that the prices of LAB are comparable and there has been no significant difference. In view of the above, it is found that the imported LAB and Domestically produced LAB have same chemical and physical characteristics except some slight differences in some of the parameters. However, the differences in parameters are not significant enough to have any bearing on competitiveness of the two products. Both the products have the capability to be used interchangeably and are being used as such. Therefore the product imported is "similar or directly competitive" to what is produced by domestic industries. Therefore, the product under investigation is LAB, as described above.

Domestic Industry:

36. The present investigation arises on an application made by M/s. Reliance Industries Ltd., Mumbai, Tamilnadu Petroproducts Ltd., Chennai, Nirma Ltd., Ahmedabad . M/s Indian Oil Corporation Ltd., New Delhi has supported the application. The shares of these companies are as mentioned below:

Table 1

	2004-05	2005-06	2006-07	2007 -08
Company	Share	Share	Share	Share
Indian Oil	11%	24%	26%	28%
Nirma	26%	21%	19%	19%
Reliance	41%	38%	36%	36%
TPL	22%	17%	19%	17%
Total	100%	100%	100%	100%

37. The share of the applicants excluding Indian Oil, who is supporting, is 72% during 2007-08 and 100% when Indian Oil is also considered along with the applicants. There has been no question raised on applicants (excluding IOC) being treated as Domestic Industry. Accordingly, the LAB businesses of M/s. Reliance Industries Ltd., Mumbai, Tamilnadu Petroproducts Ltd., Chennai, Nirma Ltd., Ahmedabad constitute domestic industry in terms of clause (b) of subsection (6) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.
38. The analysis of data has been done primarily in relation to the domestic industry only. At some places the data of IOC has also been analyzed in order to deal with the issues raised by the interested parties and to study the inter unit dynamics in India. However, in order to analyze market share of imports, complete data i.e the data including that of IOC has been used.

Period of Investigation:

39. The Customs Tariff Act, 1975, the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997, the Agreement on Safeguard and the relevant Article XIX of GATT do not specifically define what the Period of Investigation should be. However, the issue of period of investigation has been dealt extensively in the panel's report on Argentina Footwear as well as Appellate Body Report on Argentina Footwear, which are being produced below;

"ARGENTINA- SAFEGUARD MEASURES ON IMPORTS OF FOOTWEAR; Report of the Panel

8.216 *Regarding the investigation's almost exclusive reliance on end-point-to-end-point comparisons in its analysis of the changes in the situation of the industry, we have the same concerns as were noted above with regard to the "increased imports" analysis. Here we note in particular that if intervening trends are not systematically considered and factored into the analysis, the competent authorities are not fulfilling Article 4.2(a)'s requirement to analyse "all relevant factors", and in addition, the situation of the domestic industry is not ascertained in full. For example, the situation of an industry whose production drops drastically in one year, but then recovers steadily thereafter, although to a level still somewhat below the starting level, arguably would be quite different from the situation of an industry whose production drops continuously over an extended period. An end-point-to-end-point analysis might be quite similar in the two cases, whereas consideration of the year-*

to-year changes and trends might lead to entirely opposite conclusions.

8.217 *We believe that consideration of changes over the course of the investigation period in the various injury factors is indispensable for determining whether an industry is seriously injured or imminently threatened with serious injury. An end-point-to-end-point comparison, without consideration of intervening trends, is very unlikely to provide a full evaluation of all relevant factors as required*

Appellate Body Report

Note 130:

The Panel, in footnote 530 to para. 8.166 of the Panel Report, recognizes that the present tense is being used, which it states "would seem to indicate that, whatever the starting-point of an investigation period, it has to end no later than the very recent past." (emphasis added) Here, we disagree with the Panel. We believe that the relevant investigation period should not only end in the very recent past, the investigation period should be the recent past.

40. From the above it is clear that neither the Agreement on Safeguard nor the relevant provision of WTO provide specific guidelines on the period of investigation. The Appellate Body Report has given its finding in unequivocal terms that the relevant investigation period should not only end in the very recent past; the investigation period should be the recent past.
41. In the instant case, the notice of initiation was issued on 19.12.2008, which primarily contains the data up to the year 2007-08. The Preliminary Finding was issued on 30.01.2009 where the data collected for the subsequent period of 2008-09 in the course of investigation was also considered. As the Public Hearing was held on 23rd July, 2009, the information only up to 2007-08 may not be the very recent period. In other words, when the data relating to the financial year 2008-09 is available the same cannot be ignored. Hence, it is in the interest of investigation that such information is used for analysis.
42. Some of the interested parties have contended that adding new information amounts to adducing new evidence at this stage. In this respect it is noted that the Safeguard Investigation proceeding is different from the Judicial proceedings or Appellate proceedings. During the Safeguard Investigation, new facts and evidences are brought up and analyzed. In case, reliance is placed only on the facts mentioned in the application, the investigation, purpose of which is to bring

forth relevant information and analyze the market condition will become meaningless. Hence, it is necessary that all the facts brought in light during investigation are taken into account. However, the requirement of natural justice as envisaged in Rule 6 of the Safeguard Duty Rules, 1997 needs to be taken care of. Thus new facts, if not confidential, are made available to the Interested Parties by keeping the same in the Public File. In this case, all the relevant and non-confidential information has been kept in Public File and all the information, including the recent information, is being considered.

43. In order to neutralize seasonal variation, if any, sufficiently longer sample size i.e. annual data has been considered from FY 2005-06 to 2008-09.

Is there an increase in imports?

44. **Source of data:** The source of Import data is DGCIS and IBIS. Reliance has been placed on DGCIS data for the annual import figures up to 2006-07. The transaction wise import data for the period 2007-08 and 2008-09 has been provided by the applicants. The same data has also been provided to interested parties by keeping the same in Public File. No question on the correctness of the data has been raised. However, some of the interested parties have contended that some other source is giving different import figures without giving any evidence that the data source which is in Public domain is incorrect. In fact, it is noticed that some of the interested parties have also referred to the IBIS data to present their views. Therefore, the source of data relating to imports cannot be termed unreliable unless it is proved so. Therefore, the IBIS data is being used for the purpose of import analysis.

45. **Statutory framework:** The Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 provides for imposition of safeguard duty when any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to domestic industry¹. The meaning of the term 'increased quantities' has been discussed in the Panel Report and Appellate Body Report in the case of Argentina Foot Wear case. It has been held in these reports that the 'increased quantities' cannot be just any increase in imports. It must be recent and

¹ **8B Power of Central Government to Impose Safeguard Duty:** If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to domestic industry, then, it may, by notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article:

sudden². It has also been held that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause "serious injury"³.

46. **Examination of facts:** The table below shows the import statistics relating to LAB.

Table: 2

YEAR	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
IMPORTS (MT)	4871	21470	45505	73630
MARKET SHARE OF IMPORTS (%)	1.73 %	7.22 %	13.91%	21.16%

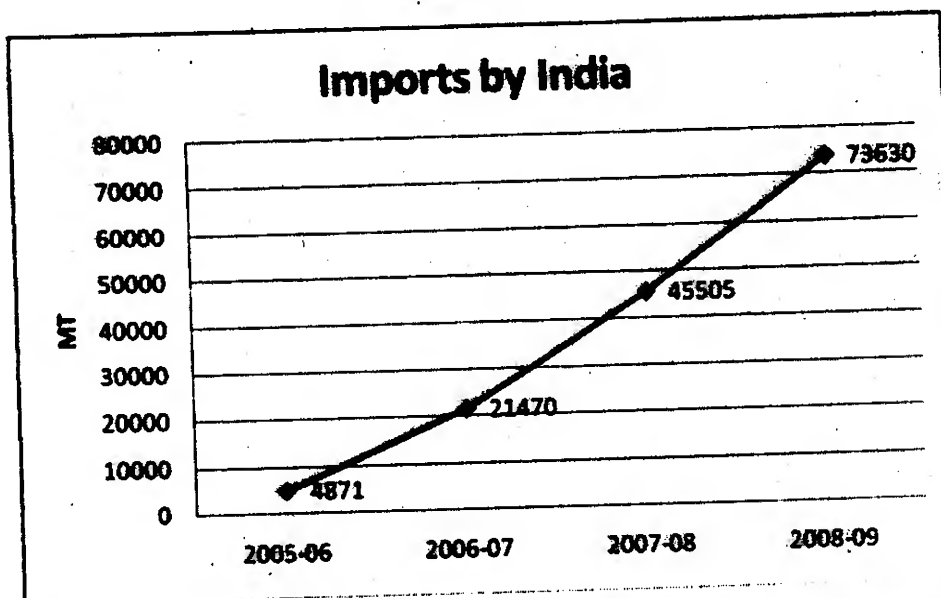
47. The total import of LAB in 2008-09 has been 73,630 MT showing increase of 28,125 MT over previous year of Import of 45,505 MT in absolute terms and 61.8% in percentage term. Except in 2005-06, there has been continuous increase in import.
48. The share of imports in the total market size also increased to 21.16% from 1.73% in 2005-06, 7.22% in 2006-07 and 13.91% in 2007-08.
49. The graph 1 below shows the nature of trend of imports. It is seen that the increase in imports is gradual since 2006-07. There is no suddenness in the growth of imports.

²Para 130 of ABR Argentina Footwear case:

"..... Although we agree with the Panel that the "increased quantities" of imports cannot be just *any* increase, we do not agree with the Panel that it is reasonable to examine the trend in imports over a five-year historical period. In our view, the use of the present tense of the verb phrase "is being imported" in both Article 2.1 of the *Agreement on Safeguards* and Article XIX:1(a) of the GATT 1994 indicates that it is necessary for the competent authorities to examine recent imports, and not simply trends in imports during the past five years – or, for that matter, during any other period of several years.² In our view, the phrase "is being imported" implies that the increase in imports must have been sudden and recent"

³ Para 131 of ABR Argentina Footwear case:

".....In our view, the determination of whether the requirement of imports "in such increased quantities" is met is not a merely mathematical or technical determination. In other words, it is not enough for an investigation to show simply that imports of the product this year were more than last year – or five years ago. Again, and it bears repeating, not just *any* increased quantities of imports will suffice. There must be "*such* increased quantities" as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry in order to fulfil this requirement for applying a safeguard measure. And this language in both Article 2.1 of the *Agreement on Safeguards* and Article XIX:1(a) of the GATT 1994, we believe, requires that the increase in imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough, and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause "serious injury".'

Graph 1

50. Therefore, it is seen that there is an increase in imports in mathematical term, but it lacks the characteristics of 'increased quantities', which must be present to qualify the context in which the term 'increased quantities' and "in such increased quantities" have been used in the statute.

Under What conditions imports are taking place?

51. The table below gives value of imports in terms of Rs/MT. The table below shows the relevant statistics.

Table 3

Year	CIF value of Imports/ MT
(Unit)	Rs
2005-06	47504
2006-07	53523
2007-08	55981
2008-09	70132

52. The CIF value increased by 25.28% in 2008-09 and by 4.6% in 2007-08. There is a consistent increasing trend in CIF value of imports over the years. Therefore, the imports are at increased prices.

Serious Injury and Causes Thereof:**Statutory framework:**

53. "Serious injury" means as an injury causing overall impairment in the position of a domestic industry;⁴
54. The Article 4.2(a) of the Agreement on Safeguard and Annexure to Rule 8 of the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997 technically requires that certain listed factors as well as other relevant factors must be evaluated to determine serious injury or threat of serious injury. However, these provisions do not specify what such an evaluation must demonstrate. Any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, there may be significant decline in sales, employment and productivity which will show "significant overall impairment" in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of all the listed factors and any other relevant factors, it is essential that the overall *position* of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.⁵
55. Accordingly, in analyzing serious injury all factors, which are mentioned in the rules as well as other factors, which are relevant, have been considered. No single factor has been considered as dispositive. All relevant factors within the context of the relevant business cycle and conditions of competition, which are relevant to the affected industry, have been considered to evaluate the overall position of the domestic industry.

Examination of factors:

56. **Rate of increase of imports:** The table below gives the information about rate of increase of imports over their previous years. It is seen that the imports increased at the rate of 61.80% in 2008-09 against 111.95% of increase in 2007-08 and 340.77% of increase in 2006-07 (compared to their previous years). The

⁴ Section 8B(6)(c) of the Customs Tariff Act, 1975.

⁵ Based on Para 139 of Argentina footwear Case Appellate Body Report Of WTO

Graph 1⁶ above shows that the increase in imports is gradual and steady since 2006-07.

Table 4

YEAR	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
IMPORTS	4871	21470	45505	73630
RATE OF INCREASE OF IMPORTS (OVER THE PREVIOUS YEAR) %	-	340.77%	111.95%	61.80%

57. **Share of the domestic market taken by increased imports:** The table below gives relevant statistics relating to Share of Total Indian LAB industry in the Indian domestic market.

Table-5

YEAR	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
MARKET SIZE(MT)	280859	297394	327116	347959
MARKET SHARE OF INDIAN PRODUCERS (%)	98.27	92.78	86.09	78.84

58. The share of the All Indian industries in the domestic market was 98.27% in 2005-06, which has gone down to 78.84% in 2008-09.
59. The reasons of loss of market share were analyzed. In 2008-09 the unutilized capacity was 81,022 MT and the imports were to the tune of 73,630 MT. It is also seen that the exports by India fell by 31,452MT during 2008-09 compared to 2007-08, which also contributed to fall in unutilized capacity. Therefore, the loss of market share is significantly attributable to factors, other than imports.
60. **Change in level of domestic sales:** The table below gives relevant statistics relating to cumulative domestic sales of the 'domestic industry' as well as of the All Indian producers (including IOC).

Table 6

YEAR	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
------	---------	---------	---------	---------

⁶ Refer para 49

SALES BY 'DOMESTIC INDUSTRY' (MT)	188942	185503	184212	169014
CUMULATIVE SALES BY ALL INDIAN PRODUCERS INCLUDING IOC (MT)	275988	275924	281611	274329

61. The sales of 'domestic industry' have shown a downward trend since 2005-06 to 2008-09.
62. The sales of all Indian producers including IOC went down by 7282 MT in 2008-09 compared to 2007-08, which constitutes 2.58%. The sales figures of past four years indicate that the cumulative sales of all Indian industries were moving in band of (+/-)1.3% of average 276963 MT.
63. **Production:** The table below gives relevant statistics relating to cumulative domestic production of 'domestic industry' and of all Indian Producers including IOC.

Table 7

YEAR	2005- 06	2006- 07	2007- 08	2008- 09
PRODUCTION BY 'DOMESTIC INDUSTRY' (MT)	356554	337808	338010	286549
CUMULATIVE PRODUCTION BY ALL INDIAN PRODUCERS INCLUDING IOC (MT)	467985	459082	470331	416316

64. The total production of 'domestic industry' fell by 51461MT in 2008-09 compared to the year 2007-08.
65. In order to analyse the inter unit dynamics of Indian LAB manufacturers and overall scenario of all domestic producers taken together, the production figures of all Indian domestic producers have also been analysed. The analysis of total production by all domestic producers (including IOC) shows that there has been improvement in production in 2007-08 by 2.45% compared to 2006-07. However, the total production fell

by 54015 MT (11.48%) in 2008-09 compared to 2007-08. The total exports fell by 31452 MT in 2008-09⁷ compared to 2007-08. This implies that the production fell by 31452 MT on account of fall in exports. The fall in production on account of reduction in export is 58.23% of the total fall in production in India. Thus, fall in exports is a significant cause of fall in production.

66. The domestic industry has accepted that one of the units was closed for a month for replacement of Heli Tower, which was not a routine maintenance. This closure led to non availability of production capacity of around 5000 MT. Therefore, closure of the unit is also one of the factors, which contributed to fall in production.
67. **Capacity Utilization:** The table below gives relevant statistics relating to capacity utilization of the domestic industry.

Table 8

YEAR	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
INSTALLED CAPACITY OF 'DOMESTIC INDUSTRY' (MT)	328500	328500	377338	377338
INSTALLED CAPACITY OF ALL INDIAN PRODUCERS INCLUDING IOC (MT)	448500	448500	497338	497338

Table 9

YEAR	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
CAPACITY UTILIZATION OF 'DOMESTIC INDUSTRY' (%)	108.54	102.83	89.58	75.94
CAPACITY UTILIZATION OF ALL INDIAN PRODUCERS INCLUDING IOC (%)	104.34	102.36	94.57	83.71

⁷ Refer Table 14 Para 76

68. The capacity utilization of "domestic industry" has shown continuous declining trend since 2005-06 to 2008-09. It is seen that there is a fall in capacity utilization in 2007-08 compared to 2006-07, despite improvement in production during the same period. The fall in capacity utilization in 2007-08 is primarily on account of increase in installed capacity of domestic industry by 48838 MT. The fall in capacity utilization in 2008-09, compared to 2007-08 is primarily on account of fall in production, which is attributable to fall in exports.
69. Similarly, the analysis of capacity utilization of all domestic producers (including IOC) also shows that the decline in capacity utilization in 2007-08 compared to 2006-07 is on account of increase in installed capacity. The decline in capacity utilization in 2008-09 is primarily on account of declining exports.
70. **Profits and Losses:** The table below gives relevant statistics relating to profit and losses of the domestic industry relating to business of LAB

Table 10

Year	Profit/MT	Profit (PBT)
(Unit)	Indexed	Indexed
2005-06	100	100
2006-07	- 25.05	- 24.5
2007-08	- 40.73	- 39.71
2008-09	+ 0.47	+0.42

71. The domestic industries suffered losses during 2006-07 and 2007-08. The loss in 2006-07 was there in spite of more than 100% capacity utilization. Hence the increased import was not the reason of loss. The imports increased during 2007-08 and 2008-09 with maximum imports in 2008-09. However, the profitability improved by 41.20 points in 2008-09, which is very significant.
72. The trend of profitability does not coincide with the trends of import. It means there are factors other than increased imports which have impacted profitability of the industry.
73. **Employment:** The applicants have submitted that the companies are multi-product companies and considering the capital intensive nature of the industry, the employment may not reflect the real extent of serious injury and threat of serious injury. The number of employees also remained stagnant, as is apparent from the table below.

Table 11

YEAR	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
NUMBER OF EMPLOYEES IN 'DOMESTIC INDUSTRY' (NO.)	1007	1007	1010	955

74. **Productivity:** The productivity of domestic industry in relation to the number of employees shows trend similar to production as it is primarily dependent on production.

Table 12

YEAR	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
PRODUCTIVITY/EMPLOYEE 'DOMESTIC INDUSTRY' (MT/EMPLOYEE)	354	335	335	300

Other factors

75. **Price Analysis:** The table below gives domestic prices of LAB. There has been continuous improvement in domestic prices since 2005-06. The price of LAB increased by 35% in 2008-09 compared to 2007-08 against 2% increase in price of LAB in 2007-08 compared to 2006-07.

Table 13

Year	Actual selling Price/MT
(Unit)	Rs
2005-06	62059
2006-07	63418
2007-08	64767
2008-09	87552

76. **Exports:** The table below gives information on exports by all Indian producers as well as by domestic industries.

Table:14
Analysis of Export Figures

YEAR	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
EXPORTS BY 'DOMESTIC INDUSTRY'(MT)	101852.32	107064.12	96855.47	82614.46
EXPORTS BY ALL INDIAN PRODUCERS INCLUDING IOC (MT)	122313.32	138368.12	135473.47	104021.46

Table 15
Export Vs Imports

Year (Unit)	Total Quantity of Exports by All Indian Producers (including IOC) (MT)	Imports by India (MT)	Net Exports by India (MT)
2005-06	122313.3	4871	117442.3
2006-07	138368.1	21470	116898.1
2007-08	135473.5	45505	89968.47
2008-09	104021.5	73630	30391.46

77. India has always been a net exporter of LAB. However, the exports from India are on the decline since 2006-07. The export from India fell by 23.22% in 2008-09 against 2% fall in 2007-08 compared to the preceding years. This led to lower production⁸ and lower capacity utilization.
78. **Inter unit dynamics amongst producers of India:** The table below gives the percentage share of individual LAB producers of India.

⁸ The total exports fell down by 31452 MT in 2008-09 compared to 2007-08. The fall in production on account of reduction in export is 58.23% of total fall in production in India.

Table: 16

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Company	Share	Share	Share	Share
Indian Oil	11%	24%	26%	28%
Nirma	26%	21%	19%	19%
Reliance	41%	38%	36%	36%
TPL	22%	17%	19%	17%
Total	100%	100%	100%	100%

79. The IOC had a mere 11% of production capacity of India, but from 2005-06 the production share is rising consistently. The Share of IOC in total domestic production reached 28% and 31% in 2007-08 and 2008-09, respectively. This rise is at the cost of other LAB producers, who constitute 'domestic industry'. This means part of the share of the 'domestic industry' has been taken by IOC.

Overall Position of the Domestic industry

80. India has been a net exporter of LAB and exported 26%, 30%, 29% and 25% of its production in 2005-06, 2006-07, 2007-08 and 2008-09 respectively. This shows that export of LAB is an important business of Indian Industries of LAB. The installed capacity was expanded in 2007-08 by 48838 MT but the production could increase only by 11,249 MT, which caused fall in capacity utilization to below 100% (94.57%).
81. The year 2008-09, witnessed fall in exports by 31,452 MT, which made surplus capacity available for domestic market. As imports were necessary to meet increasing domestic demands till 2007-08, the trend of import continued to meet the domestic demand, which grew by 20,843 MT. The Indian industries were not able to quickly regain the domestic market, which had been left for imports, as changes in buying patterns are generally gradual. This fact is visible from the graph 1⁹, which shows that the growth in imports is linear and there is no sharp or sudden increase in imports since 2005-06. In fact, there is no sudden surge in the

⁹ Refer Para 49

rate of increase of imports. As a matter of fact the rate of increase of imports over previous years is less in 08-09 (61.80%) as compared to 07-08(111.95%) and 2006-07 (340.77%).

82. The loss of export market by the Indian Industries could not be compensated by the corresponding gain in domestic market. This is evident from the fact that total domestic sales by all the domestic producers remained range bound. It is also observed that the year 2007-08 witnessed fall in export by 2895 MT and increase in domestic sales by 5687 MT even though installed capacity expanded by 48838 MT. The year 2008-09 witnessed further fall in exports by 31452 MT compared to 2007-08, without corresponding gain in domestic sales during the same period.
83. The Section 8B of the Customs tariff Act, 1975 provides for imposition of safeguard duty in case any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause serious injury to domestic industry. In other words safeguard duty can be imposed when increased imports is the substantial cause of serious injury. The determination of serious injury is based on evaluation of various economic factors. It is seen from the analysis done above that each of the individual factors, which are analysed to determine existence of serious injury, is significantly attributable to factors other than increased imports.
84. The analysis of trend of import, and other economic factors shows that there are factors, other than increased imports, which have significantly affected the performance of domestic industry. These are
- a. entry of IOC in LAB business;
 - b. fall in exports; and
 - c. export oriented design of domestic producers;
85. As discussed in the analysis of various economic factors above, contribution of these factors in affecting the domestic market are more significant than the increased imports. Therefore, there is a lack of causal link as required under law. Moreover, the overall evaluation does not show serious injury.

Conclusion and Recommendation:

86. Based on the above, no safeguard duty on imports of LAB is recommended.

[F. No. D-22011/23/08]

PRAVEEN MAHAJAN, Director General